लखनऊ

शुक्रवार, 26 जून, 2026

वर्ष : 11 | अंक: 300

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

सपनों की उड़ान वही भरते हैं, जिनके पंख हौसलों से बने होते हैं।

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

भरत तिवारी एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, CM बोले- 'भोजपुर में एक'

नई दिल्ली, एजेंसी। भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर गुरुवार (25 जून, 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आई। वे पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई भी समस्या सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर उसको आगे बढ़ाती है। सम्राट चौधरी ने कहा, 'भोजपुर में एक घटना घटी... तुरंत बिहार सरकार ने ज्यूडिशियल कमीशन का गठन किया। क्योंकि न्याय मिले..कोई अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई हो...' सम्राट चौधरी ने उक्त बयान एक कार्यक्रम के जरिए तब दिया जब इस केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले जब वे मीडिया के सामने आए थे तो पत्रकारों ने उनसे भरत तिवारी केस पर सवाल किया था तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। अब एक कार्यक्रम के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि सरकार कैसे चिंतित है। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें भोजपुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की मुहर लगी थी। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को जांच की जिम्मेदारी मिली है। आज (गुरुवार) विनोद सिन्हा बिलौटी गांव भी गए थे। परिजनों से वे मिले हैं।

कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान शुरू, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक माफिया की जांच की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज नामक अभियान का शुभारंभ किया। यह 40 दिनों का अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा। यह अभियान उन छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी मेहनत पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी, भर्ती अटकने और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही है। छात्र निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज आंदोलन के तहत छात्रों से जुड़ने की अपील की है, जिसके तहत एक मिस्ड कॉल नंबर -9873036161 जारी किया गया है साथ ही छात्रों से छात्रों की गूंज डॉट आई एन पर जाकर रजिस्टर करने की अपील की गयी है। देश के 28 शहरों में चल रहे इस जनांदोलन से जुड़कर अपने शहर में छात्रों की गूंज चैप्टर का हिस्सा बन सकते है। क्योंकि ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं बल्कि युवा भारत के सपनों को बचाने का छात्र आंदोलन है। गौरव गोगोई ने कहा कि नीट यूजी 2026 ने परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का संकट और गहरा कर दिया है। भाजपा सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को पारदर्शिता और सुधार के नाम भारत के छात्रों पर थोपा था, लेकिन यह संस्था आज करोड़ों छात्रों के लिए नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है। देशभर में पिछले वर्षों में लगभग 89 से अधिक पेपर लीक और परीक्षा घोटाले सामने आए, लेकिन आज तक किसी बड़े सरगना, राजनीतिक संरक्षण देने वाले व्यक्ति या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं हुआ।

आपातकाल था लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय: मोदी बोले- संविधान को कुचल दिया गया था

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दौर बताया है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला है।पीएम मोदी ने कहा कि उस समय संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला किया गया था। यह दिन देश के इतिहास का काला अध्याय था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाए गए और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा रहा था। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला दौर क्या होगा। पीएम मोदी ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि यह दौर उन लाखों भारतीयों के साहस का प्रतीक है, जिन्होंने दबाव के बावजूद संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाई।

संविधान हमारी ताकत का प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। उन्होंने देशवासियों से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि 'संविधान हत्या दिवस' हमें उस काले दौर की याद दिलाता है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह कुचल दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह दिन लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा देता है।

21 महीने तक लागू रहा था आपातकाल

भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू रहा। इस दौरान केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां मिल गई थीं और कई संवैधानिक सुरक्षा उपायों को निलंबित कर दिया गया था।

प्रेस पर नियंत्रण और विवादित फैसले

आपातकाल के दौरान प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। कई संवैधानिक संशोधन किए गए, जिनसे न्यायपालिका और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्तियां प्रभावित हुईं। इसी अवधि में जबरन नसबंदी अभियान भी सबसे विवादित मुद्दों में शामिल रहा।

कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार

कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर पिछले 11 वर्षों के शासनकाल में संसद को कमजोर करने, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में अब एक "अघोषित आपातकाल" (undeclared emergency) लगा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा पुरानी बातों (1975 के आपातकाल) का बार-बार इस्तेमाल कर रही है।

सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने के लिए ‌"सत्ता के अहंकार" में यह आपातकाल लगाया था। सीएम योगी ने एक्स पोस्ट में कहा, "25 जून, 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब 'आपातकाल' थोप कर देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। सत्ता के अहंकार में कांग्रेस द्वारा थोपे गए 'आपातकाल' के अंधकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व नागरिक अधिकारों को गहरी चोट पहुंचाई। उस कठिन दौर में कठोर यातनाएं सहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सभी महान लोकतंत्र सेनानियों को कोटिशः नमन"।

अमित शाह ने भी इमरजेंसी को काला इतिहास बताया

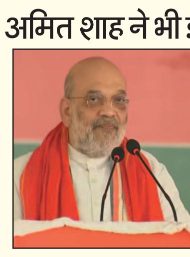

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इमरजेंसी को काला इतिहास बताया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के सत्ता के अहंकार और लालच ने संविधान की आत्मा, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने का प्रयास किया था। संविधान हत्या दिवस के अवसर पर लोकतंत्र के उन सभी सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। मोदी सरकार द्वारा 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का उद्देश्य इस काले अध्याय को राष्ट्र की स्मृति में जीवित रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान पर ऐसा आघात कभी दोबारा न कर सके"।

पीएम मोदी के बाद अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच हुई है।

राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा, 'केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।' इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी।

इन बैठकों को संभावित मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाल में केरल से भाजपा के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। वह अल्पसंख्यक तथा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री थे। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए पुनः उम्मीदवार नहीं

इसके अलावा, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह का भी राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें उच्च सदन के लिए दोबारा नामित नहीं किया गया है। वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं। वह अगस्त 2024 में राजस्थान से उच्च सदन के लिए चुने गए थे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उनके गृह राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को और बल मिला है।

नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है पासपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर यह बात कही कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है नागरिकता का सबूत नहीं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ गई और लोग पूछने लगे कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं हैं तो फिर असली सबूत क्या है।

पासपोर्ट का नागरिकता का सबूत न होना कोई नई बात नहीं है। यह बात सालों से कानून में लिखी हुई है। पासपोर्ट को लेकर एक बात बार-बार कही जाती है कि यह किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का सबूत है, लेकिन कानूनी तौर पर यह बात सही नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। यह कोई नई बात नहीं है यह बात सालों से कानून में लिखी हुई है।

PMO के दखल के बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट का इनकार, नहीं देंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से मिली शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगी गई विस्तृत वित्तीय जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने 9 जून को PMO को पत्र लिखकर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की थी। शिकायत में राम मंदिर ट्रस्ट के बनने के बाद से आय और खर्च में पारदर्शिता की मांग की गई थी। साथ ही, मिले दान, बैंक अकाउंट के कामकाज, ज़मीन की खरीद-बिक्री और कुल संपत्ति का ब्योरा भी मांगा गया था।इसके बाद PMO ने यह मामला ज़िला प्रशासन को भेज दिया, जिसने ट्रस्ट से ज़रूरी जानकारी मांगी। हालांकि, खबरों के मुताबिक ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड शेयर करने से इनकार कर दिया। अपने जवाब में ट्रस्ट ने कहा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पहले से ही औपचारिक जांच कर रही है और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। इसलिए, इस स्टेज पर और जानकारी शेयर करना सही नहीं होगा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 13 जून को गठित SIT ने इस हफ़्ते की शुरुआत में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मूल शिकायत में 'समर्पण निधि' अभियान के तहत जुटाए गए फंड का ब्योरा, सोने, चांदी और गहनों के रूप में मिले दान की जानकारी, साथ ही ट्रस्ट के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वित्तीय लेन-देन और ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करने की भी मांग की गई थी।

'डिजिटल अरेस्ट' पर CBI का बड़ा एक्शन, दिल्ली-पंजाब से लेकर बंगाल तक 16 राज्यों में छापेमारी

नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर लोगों को ठगने वाले एक बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में सीबीआई ने 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस संगठित नेटवर्क ने 200 से अधिक मामलों में लोगों को धोखा देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी वेबसाइट का सहारा लिया था।

यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच एजेंसी ने एक ऐसी फर्जी वेबसाइट का खुलासा किया, जिसका वेब एड्रेस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा था। जालसाज इसी डोमेन का उपयोग करके कानूनी अधिकार होने का झूठा दिखावा करते थे और पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट की धमकियां देकर डराते थे। अपनी धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए आरोपी फर्जी अदालती आदेश और जांच एजेंसियों के जाली दस्तावेज भी अपलोड करते थे।

इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र-VI के तहत 60 विशेष टीमों का गठन किया। इन टीमों ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा में एक साथ छापेमारी की। इस अभियान के दौरान चेन्नई से बी। नरेश और कोलकाता से संजीब साहा को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, ये दोनों शेल कंपनियां बनाने और म्यूल बैंक खाते खोलने व संचालित करने में शामिल थे, जिनका उपयोग अपराध से कमाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए किया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले तार

उन्नत तकनीकी विश्लेषण और फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, जांचकर्ताओं ने इस साइबर अपराध के पूरे बुनियादी ढांचे की पहचान की है, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी संचालित हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह ने केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के लोगों को भी निशाना बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई टीम, राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे को बनाया गया उपाध्यक्ष

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की नई टीम का ऐलान हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत करके आईं पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में कुल 46 लोगों के नाम शामिल हैं। नीरज को यह स्थान उनके भाई पंकज सिंह की जगह मिला है। पार्टी ने कुल 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 लोगों को मंत्री बनाया गया है। भाजपा ने पश्चिमी प्रदेश का अध्यक्ष नबाब सिंह नागर, ब्रज प्रदेश का पूरन लाल लोधी, कानपुर का राम किशोर साहू, अवध क्षेत्र का अवधेश द्विवेदी, काशी का अशोक चौरसिया और गोरखपुर का विनोद राय को बनाया है। भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष रोहित मिश्रा, महिला मोर्चा का सरोज कुशवाह और अनुसूचित जनजाति मोर्चा का विद्याभूषण गोंड को बनाया है।

शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने किया मानहानि केस तो राहुल गांधी ने जताया खेद

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से जुड़ी कथित मानहानि वाली टिप्पणी पर खेद जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया है। कार्तिकेय सिंह ने भोपाल की एक अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि 2018 में झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान पनामा पेपर्स विवाद का ज़िक्र करते हुए राहुल गांधी ने उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। बुधवार को अपने वकील के ज़रिए दायर अर्ज़ी में गांधी ने कहा कि उनकी टिप्पणी कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं थी। शिकायत के बाद, भोपाल की अदालत ने गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया। इसके बाद उन्होंने समन और मानहानि की कार्यवाही, दोनों को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल करेंगे। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश किए। शिकायतकर्ता की ओर से वकील संकल्प कोचर पेश हुए।

यह मामला 2018 में झाबुआ में हुई एक चुनावी रैली के भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स विवाद का ज़िक्र करते हुए कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिससे उनकी बदनामी हुई।

मुंबई में जमकर बरस रहा मानसून: दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, IMD की चेतावनी जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के वित्तीय केंद्र मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई की सड़कों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी मौसम बुलेटिन जारी कर देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का 'ऑरेंज और येलो अलर्ट' जारी किया है।

देर से आए मानसून ने देश की आर्थिक राजधानी को पानी-पानी कर दिया। शहर के कुछ हिस्सों में सुबह आठ बजे तक 24 घंटों के दौरान 300 मिमी से ज्यादा बारिश हुई। मंगलवार से शुरू हुई भारी बरसात ने बुधवार को मुंबई और उसके उपनगरों की रफ्तार धीमी कर दी।

सामान्य रूप से चहल-पहल भरी जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई, सड़क और रेल यातायात बाधित हो गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। भीषण सूखे से कराह रहे मराठवाड़ा में भी मंगलवार से मानसून ने दस्तक दे दी है। प्याज मंडी के रूप में मशहूर नासिक के लासलगांव से लेकर कपास उत्पादक क्षेत्र बुलढाणा एवं जालना में हुई अच्छी वर्षा ने किसानों को राहत दी है।

दिल्ली-एनसीआर और यूपी में छाए रहेंगे बादल, आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर में अगले 48 घंटों के भीतर तेज ठंडी हवाओं (40-50 किमी/घंटा) और गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी मानसून की दस्तक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्री-मानसून और मानसूनी हवाओं का संयुक्त असर है, जिससे भीषण गर्मी और उमस झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।

इन 17 राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट

आईएमडी ने जिन 17 राज्यों में आगामी 3 से 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान।

पश्चिम और मध्य भारत: महाराष्ट्र (मुंबई और कोंकण), मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय।

दक्षिण भारत: केरल, कर्नाटक (तटीय क्षेत्र) और गोवा।

वायरल वीडियो पर CM भगवंत मान बोले, 'मेरे गले पर बचपन से एक निशान, मगर इसमें नहीं'

नई दिल्ली, एजेंसी। बेअदबी विवाद पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल तीनों को निशाने पर लिया। मोहाली में गुरुवार (25 जून) को उन्होंने कहा कि ये सब लोग मुझसे हार गए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सब मिलकर मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां मिलकर उनके पीछे पड़ी हैं। सीएम मान ने फिर कहा, 'मुझे बदनाम करने के लिए एक फर्जी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है। मुझे बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाएं जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। धार्मिक तौर पर मुझे बदनाम करने की साजिश की गई। यह वीडियो मुझे सियासी तौर पर बदनाम करने के लिए बनाया गया है। सियासी फायदे के लिए फर्जी वीडियो बनाए गए।

आजम को झटका: जौहर ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर पड़ेगी भारी आयकर की मार! लगाई जा सकती है बड़ी पेनाल्टी

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। आयकर विभाग ने जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद ट्रस्ट पर भारी कर और पेनाल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि, ट्रस्ट के पास ट्रिब्यूनल में अपील करने का विकल्प खुला है।

आयकर विभाग ने यह कार्रवाई सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां से जुड़े जौहर ट्रस्ट पर की है। यह निर्णय वर्ष 2023 में आयकर छापों के दौरान मिली गड़बड़ियों के आधार पर लिया गया है। विभाग ने ट्रस्ट से इन गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन ट्रस्ट तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

जीएसटी और आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता के अनुसार, आयकर विभाग ने ट्रस्ट का 12एबी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अब ये ट्रस्ट चैरिटेबल नहीं रहेगा। इससे ट्रस्ट की पूरी कमाई को अब एक सामान्य कारोबार की तरह माना जाएगा।

ट्रस्ट की आय पर सामान्य व्यावसायिक दरों से भारी कर वसूला जा सकता है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आयकर विभाग ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करेगा। इसमें जमीन, इमारत और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

इसके अलावा, विभाग कार्रवाई की अवधि से लेकर अब तक की आय, चंदे और संपत्ति पर भारी कर के साथ ब्याज और पेनाल्टी भी लगा सकता है। ऐसा होने पर में ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ना तय है। गौरव गुप्ता के अनुसार 12एबी का पंजीकरण मुख्य रूप से एनजीओ, ट्रस्ट, और गैर-लाभकारी संगठनों के लिए होता है। इसे प्राप्त करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि संगठन को अपनी प्राप्त आय (दान या अनुदान) पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता, बशर्ते उस धन का उपयोग सामाजिक या धार्मिक कार्यों में किया गया हो।

पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिजनों के जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आयकर विभाग ने निरस्त कर दिया है। विभाग ने ट्रस्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की है। वर्ष 2023 में जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग के छापों में ट्रस्ट द्वारा की गईं गड़बड़ियों की गहन जांच के बाद रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है। जांच में ट्रस्ट की गतिविधियां अवास्तविक पाई गईं, जो पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन था।

आयकर विभाग, लखनऊ के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय) गौरव बॉथम ने बीते दिनों ट्रस्ट पर लगे तमाम आरोपों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद बुधवार को रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। इस बीच विभाग ने ट्रस्ट के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई तथा उसके बाद की विभागीय जांच के दौरान विभिन्न तथ्यों और दस्तावेजों का परीक्षण किया था।

जिसमें ट्रस्ट के अभिलेख, लेखा-जोखा एवं अन्य सामग्री शामिल थी। इस दौरान तमाम अनियमितताएं और तथ्य मिले, जिनका संज्ञान लेकर आयकर विभाग ने जांच में शामिल किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। साथ ही जौहर ट्रस्ट पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों का भी संज्ञान लिया। बता दें कि इस प्रकरण की शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आयकर विभाग से की थी। ट्रस्ट द्वारा रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी (निजी) का निर्माण कराया गया था।

इन गड़बड़ियों की वजह से हुई कार्रवाई

मंत्री रहने के दौरान पद का दुरुपयोग कर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराना।

यूनिवर्सिटी परिसर में मस्जिद और सपा कार्यालय के भवन का निर्माण।

अनुमति से अधिक सरकारी भूमि पर काबिज होना।

यूनिवर्सिटी में बने 59 भवनों की लागत को 10 गुना कम करके बताना।

बोगस डोनेशन लेना, डमी ट्रस्टी बनाना।

ट्रस्ट द्वारा जनहित में कोई भी काम नहीं करना।

भवनों के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक बैंकों में आय से अधिक नगदी जमा कराना।

दान की रकम को स्वेच्छा के बजाय जबरदस्ती जमा कराना।

बिना हिसाब-किताब वाली रकम को दान दिखाकर खाते में जमा कराना।

भवनों के निर्माण के लिए विभागों से आवश्यक अनुमतियां नहीं लेना।

अग्निशमन के मानकों का पालन नहीं करना।

ट्रस्ट में आजम खां के परिजनों का काबिज होना।

पूजा पाल और डॉ कृतिका बनी भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। पार्टी ने 64 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है, जिसमें संगठन और विभिन्न मोर्चों में कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नई सूची में कुल 52 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इनमें 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 अन्य पदाधिकारियों को भी संगठन में स्थान दिया गया है।

भाजपा की नई टीम में प्रयागराज से जुड़े नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं विधायक पूजा पाल को पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है।

जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध कारोबार पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अधिवक्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई कथित मारपीट की घटना पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, 21 जून की रात रेलवे स्टेशन स्थित लक्ष्मी भोजनालय में अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह, विपिन पाण्डेय और राजन पाठक पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्टेशन रोड और कुड़वार नाका क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होटल और दुकानों के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से दबंगई, मारपीट और अवैध वसूली जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद हैं। घटना को लेकर अधिवक्ता समुदाय में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की कि मामले में नामजद और शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, गंभीर धाराओं के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, क्षेत्र में संचालित अवैध दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें हटाया जाए तथा घायल अधिवक्ता की सुरक्षा और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

कंपोजिट ठेके पर उठे सवाल, प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

सुलतानपुर। पुलिस लाइन और एसपी आवास के बीच संचालित कंपोजिट ठेके को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी और सवाल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सुबह से देर रात तक यहाँ भीड़ और शराबखोरी का माहौल बना रहता है, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है।

कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि आने-जाने वाली महिलाओं और बच्चियों को असहज स्थिति और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो संबंधित विभागों को जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि संवेदनशील क्षेत्र होने और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की आवाजाही के बावजूद लोगों को स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा।

SIT के सामने पेश हुए संजय सिंह : बोले– आठ करोड़ में खरीदी गई चार करोड़ की जमीन, महाघोटाला हुआ, सबूत सौंपे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बृहस्पतिवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच समिति के मुखिया विजय विश्वास पंत के सामने पेश हुए और अयोध्या में जमीनों की खरीद में हुए घोटालों का सबूत दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद में महाघोटाला हुआ है। चार करोड़ की जमीन कुछ ही दिनों के बाद आठ करोड़ में खरीदी गईं और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जुड़े लोग शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि महाघोटाले से जुड़े सबूत दस्तावेजों के रूप में एसआइटी को सौंप दिए गए हैं जिस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के नाम पर महाघोटाला हुआ है।

एसआईटी रिपोर्ट ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बीच एक ऐसा तथ्य सामने आया है, जिसने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2020 में ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीनों बाद निजी ऑडिट फर्म ने दान प्रबंधन, आभूषणों के रिकॉर्ड, वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर संकेत कर सुधार की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक फर्म ने रिपोर्ट में कहा था कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए जरूरी अभिलेखों का अभाव है और प्रबंधन की जवाबदेही तय करने वाली स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े गंभीर सवाल उठे हैं, ऐसे में छह साल पुरानी इस ऑडिट रिपोर्ट को अपनी जांच का अहम आधार बन सकती है।

सबकुछ पता था तब भी की अनदेखी : ट्रस्ट को चेताया गया था कि बिना मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना कठिन होगा। फर्म ने लेन-देन, डाटा प्रबंधन, मानव संसाधन और रिकॉर्ड संधारण के लिए विस्तृत एसओपी लागू करने की सिफारिश की थी।

फर्म ने सबसे गंभीर टिप्पणी दान और आभूषणों के रिकॉर्ड को लेकर की

फर्म ने सबसे गंभीर टिप्पणी दान और आभूषणों के रिकॉर्ड को लेकर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नकदी के अलावा प्राप्त होने वाले दान के लिए समुचित स्टॉक रजिस्टर और निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। बैंक समन्वयन और वित्तीय निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी भी चिन्हित की गई थी। डेटा सुरक्षा और आईटी नियंत्रण को लेकर भी फर्म ने चिंता जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा, डेटा एंट्री की निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए पर्याप्त नियंत्रण तंत्र मौजूद नहीं था।

रविवार को आयोजित होगा रक्तचाप पर प्रदेश स्तरीय सेमिनार

सेमिनार में देश के कोने-कोने से हृदय रोग विशेषज्ञ लेगे भाग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। आगामी 28 जून को रविवार को स्टेट मेडिकल कॉलेज दुबेपुर में इंडियन सोसायटी आफ हाइपरटेंशन के यू पी चैप्टर की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कि जिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 12000 बजे प्रोफेसर आरके धीमान और पद्मश्री एसबीआई एसजीपीजीआई के डायरेक्टर करेंगे और प्रोफेसर के के त्रिपाठी पद्मश्री जो नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह का नोट व्याख्यान होगा। जोकि भू सेंड नेफ्रोलॉजी में बोलेंगे और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य कपूर, डॉ जुमानी और डॉक्टर सादिक अंसारी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, प्रोफेसर अवधेश शर्मा, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर सोनकर स्पीकर्स के काफी अच्छे सीएम होंगे। कार्यक्रम 7.00 बजे सुबह स्टार्ट होगा 12.00 बजे उद्घाटन होगा और शाम को 5.00 बजे समाप्त होगा इस कार्यक्रम में सभी तरह के डॉक्टर आयुर्वेद होम्योपैथिक और मॉडर्न मेडिसिन के सभी डेलिगेट्स इनवाइटेड है और ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ही अच्छा आधुनिक व्याख्यान दिया जाएगा जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं वहां पहुंचे सेमिनार को सफल बनाने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुल्तानपुर के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का सारणी सहयोग मिल रहा है। आशीर्वाद हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ एके सिंह सचिव डॉक्टर अंकुर सेठ वरिष्ठ नाक कान गला रोग सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जेपी सिंह फिजिशियन डॉक्टर राजीव रतन मिश्रा की उपस्थिति सराहनीय रही।

पालिकाध्यक्ष ने दी विकास की सौगात, 45 लाख की लागत से सड़क व नाली निर्माण का शुभारंभ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शहर के आदर्श नगर वार्ड में वर्षों से जर्जर पड़े मार्ग को अब नई पहचान मिलने जा रही है। नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर द्वारा पल्टू का पुरवा तिराहे से एमएसबी स्कूल (मधुसूदन इंटर कॉलेज मार्ग) तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन कर शुभारंभ किया गया। भूमिपूजन कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय सभासद एवं क्षेत्रीय नागरिक लंबे समय से सड़क पुनर्निर्माण और जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। नगर पालिका ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा, जिसके बाद पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत लगभग 45 लाख रुपये की लागत से 317 मीटर लंबी सीसी सड़क एवं नाली निर्माण को स्वीकृति मिली। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि नगर क्षेत्र में सड़क, नाला-नाली निर्माण एवं प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण सहित विकास कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। नगर पालिका स्वच्छ सुंदर सुल्तानपुर की संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। कार्यक्रम का संयोजन स्थानीय सभासद विजय कुमार जायसवाल ने किया। इस दौरान सभासद मंगरू प्रसाद प्रजापति सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

महिला मित्र की कार से बैंक में ठगी करने वाला मोहित दिल्ली व हरियाणा पुलिस के रडार पर, प्रेम जाल में फंसाकर करता था जालसाजी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। आइसीआइसीआइ बैंक कर्मचारी से चार लाख रुपये की ठगी के मामले में गोरखनाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया मोहित चावला शातिर ठग निकला। इसके विरुद्ध हरियाणा और दिल्ली में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

गिरफ्तारी के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से संपर्क किया है। इधर, गोरखनाथ पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपित लंबे समय से ठगी का काम कर रहा था। इसके लिए वह महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देता था। गोरखपुर भी वह महिला मित्र की कार से आया था। पुलिस के अनुसार, मोहित चावला के विरुद्ध हरियाणा और दिल्ली के अलग-अलग थानों में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जालसाजी और चोरी जैसे गंभीर अपराध में केस दर्ज हैं। लंबे समय से फरार इस आरोपित की तलाश में दोनों राज्यों की पुलिस जुटी हुई थी।

गोरखपुर में गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस की टीम भी शहर पहुंच गई और उसके आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाई। इसके अलावा पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि बैंक कर्मचारी से ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए मोहित अपनी एक महिला मित्र की कार लेकर गोरखपुर आया था। घटना के बाद पुलिस ने सीसी कैमरे के फुटेज और वाहन नंबर के आधार पर जांच शुरू की, जिससे वाहन के मालिकाना हक का पता चला।

इसके बाद संबंधित महिला से संपर्क किया गया, जहां से पुलिस को कई अहम जानकारियां सामने आईं। आरोपित ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित आइसीआइसीआइ बैंक शाखा के कर्मचारी यश चौधरी को एफडी कराने का झांसा देकर चार लाख रुपये की ठगी की गई थी। आरोपित ने खुद को बैंक अधिकारियों का परिचित बताकर विश्वास में लिया और छोटे नोट बदलवाने के बहाने पूरी रकम लेकर फरार हो गया।

मामले की जांच में सीसी कैमरे के फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बिजनौर निवासी मोहित चावला और उसके साथी रोहित यादव को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से ठगी की रकम में से दो लाख रुपये बरामद किए गए थे। पुलिस अब आरोपित के अन्य मामलों और राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच कर रही है।

गोरखपुर में भी है आरोपित की महिला मित्र

पुलिस के अनुसार आरोपित मोहित खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाता था। दोस्ती और प्रेम संबंध का भरोसा दिलाकर वह उनके वाहन, बैंक खाते और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल अपने ठगी नेटवर्क में करता था। कई मामलों में पीड़ित महिलाओं को यह भी पता नहीं होता था कि उनके नाम या संसाधनों का उपयोग अपराध में किया जा रहा है।X

कैंट क्षेत्र में स्थित होटल में दो दिन तक ठहरने के दौरान उसके संपर्क में शहर की एक महिला मित्र भी रही। इसके अलावा बैंक से ठगी के रुपये में दो लाख रुपये उसने लखनऊ की एक महिला मित्र को दिया था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ठगी के रुपये को लेकर महिला मित्र फरार हो गई थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

गोरखपुर में भूमि का अड़ंगा, अमृत 2.0 योजना की रफ्तार पर ब्रेक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। महानगर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अमृत 2.0 योजना भूमि की उपलब्धता के अभाव में अटक गई है। योजना के तहत प्रस्तावित 28 ओवरहेड टैंक और नलकूपों के निर्माण के लिए अब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है।

नगर निगम से भूमि नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) निर्माण खंड प्रथम ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र भेजकर तत्काल भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। समय पर जमीन नहीं मिली तो शहर के कई क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति का इंतजार और लंबा हो सकता है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत गोरखपुर पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज-3 एवं 4) में नगर निगम के विस्तारित और घनी आबादी वाले इलाकों में नई पेयजल संरचनाएं विकसित की जानी हैं। बढ़ती आबादी और शहर के विस्तार को देखते हुए योजना को अहम माना जा रहा है। जल निगम ने योजना के लिए कुल 47 स्थानों पर सरकारी अथवा निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा था।

> **जल निगम की ओर से अमृत योजना के तहत भूमि की मांग की गई है। इस संबंध में पत्र आया है। भूमि मिल जाने के बाद यह परियोजना तैयार करेंगे। नगर निगम और राजस्व विभाग की ओर से भूमि चिह्नित किया जाएगा।**
>
> **- रघुवेंद्र कुमार, जलकल महाप्रबंधक**

तहसील सदर की जांच के बाद इनमें से केवल 19 स्थानों पर ही भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। शेष 28 स्थानों पर भूमि विवाद, अभिलेखीय दिक्कत या जमीन उपलब्ध न होने के कारण निर्माण की शुरुआत नहीं हो पा रही है।

जल निगम के अधिकारियों के अनुसार जमीन नहीं मिलने से टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई चिह्नित संपत्तियों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने, श्रेणी परिवर्तन और हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाएं भी पूरी नहीं हो सकी हैं। ऐसे में कागजों में उलझी जमीन के कारण धरातल पर योजना की रफ्तार थम गई है।

आठ नए ओवरहेड टैंक समेत कई संरचनाओं का होना है निर्माण

जल निगम के अधिकारियों के अनुसार योजना के तहत शहर में आठ नए ओवरहेड टैंक बनाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा 28 स्थानों पर ओवरहेड टैंक और नलकूप प्रस्तावित हैं। साथ ही पांच अंडरग्राउंड टैंक भी बनाए जाने की योजना है। इन टैंकों का निर्माण भी भूमि उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। वहीं, नगर निगम के 12 हैंडपंपों को भी जल निगम की ओर से हैंडओवर लिया जाना है, जिससे पेयजल व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। लेकिन भूमि की समस्या दूर नहीं होने से पूरी योजना की गति प्रभावित हो रही है।

जल निगम ने नगर निगम से मांग की है कि जिन 19 स्थानों पर सहमति बन चुकी है, वहां जल्द कब्जा दिलाकर अभिलेखीय प्रक्रिया पूरी कराई जाए। साथ ही शेष 28 स्थानों के लिए विवाद रहित वैकल्पिक सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि अमृत 2.0 योजना समय सीमा में पूरी हो सके और शहरवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सके।

'आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय, कांग्रेस ने सत्ता के लिए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का किया गला घोंटा'

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा, नागरिक अधिकारों को कुचला और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई बताना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र के महत्व और उसकी रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को भुलाया न जा सके।मुख्यमंत्री गुरुवार को लखनऊ में आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' एवं 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया और उनके योगदान को लोकतंत्र की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को दबाने का काम किया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाए गए और हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पूरे देश को भय और दमन के वातावरण में झोंक दिया था।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज संविधान की दुहाई देने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि आपातकाल के दौरान उसी संविधान की आत्मा को सबसे अधिक चोट पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय रातों-रात संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किए गए और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस आज भी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन नेताओं ने कभी कांग्रेस की नीतियों और आपातकाल का विरोध किया था, आज उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाले लोग उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोकतांत्रिक संघर्षों और सिद्धांतों के साथ समझौता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भारतीय परंपरा में लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और केंद्र तथा प्रदेश सरकार इसी भावना के साथ कार्य कर रही हैं।उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास, शौचालय, रसोई गैस, निःशुल्क राशन और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना लोकतंत्र के प्रति सरकार की जवाबदेही का प्रमाण है। करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की नकदरहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराने की व्यवस्था भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने देश और संविधान की रक्षा के लिए जेलों में यातनाएं सहीं, अपमान झेला और अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में समर्पित कर दिए। ऐसे लोगों का सम्मान करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान समय में 3,780 लोकतंत्र सेनानी तथा 1,461 आश्रित लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2018 से लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये सम्मान राशि दी जा रही है। साथ ही उन्हें राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा और सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।समारोह में लोकतंत्र सेनानी भारत दीक्षित, गया प्रसाद सोनकर, राम सिंह कुशवाहा, विद्याराम वर्मा, अजय सिंह और ओमप्रकाश गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल के दौर की अपनी पीड़ा और संघर्षों को भी साझा किया।लोकतंत्र सेनानी भारत दीक्षित ने बताया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को निर्ममता से प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक संघर्ष नहीं छोड़ा। वहीं विद्याराम वर्मा ने कहा कि आज भी आपातकाल की यादें उन्हें भावुक कर देती हैं। उन्होंने बताया कि विरोध करने वालों के घरों पर रात में छापे मारे जाते थे, लोगों को जेलों में बंद किया जाता था और कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं।समारोह में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोकतंत्र सेनानी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों के योगदान को याद करते हुए नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

युवती से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने, उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लंबे समय तक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला एवं बाल सुरक्षा अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई को पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अमित कुमार आनंद के पर्यवेक्षण में सरोजनीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की निगरानी अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक पाण्डेय द्वारा की जा रही थी।पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को पीड़िता ने सरोजनीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अम्बुज वर्मा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जितनी आबादी, उतना हक' के नारे के साथ कांग्रेस ने मनाया शाहूजी महाराज जयंती समारोह

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग और अनुसूचित जाति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक न्याय के अग्रदूत और आरक्षण व्यवस्था की नींव रखने वाले राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती 'आरक्षण दिवस : जितनी आबादी, उतना हक' के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, आरक्षण और वंचित वर्गों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि शाहूजी महाराज ने अपने समय में जाति-पाति, ऊंच-नीच, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए पिछड़े, दलित और वंचित समाज को शिक्षा, सम्मान और

भागीदारी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व आज भी देश के सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार और हिस्सेदारी दिलाने की मांग को मजबूती से उठा रहा है।अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए वंचित वर्गों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखनी होगी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने संबोधन में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना निर्णय सुनाएगी।

जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें अधिकारी : ए.के. शर्मा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि जनता की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा और नगर विकास विभाग से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जनसुनवाई में बड़ी

संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। इनमें नगर निकायों की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की समस्याएं, विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं क्षमता वृद्धि, विद्युत आपूर्ति में बाधा, आवास योजनाओं का लाभ, सड़क निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था से जुड़े प्रकरण प्रमुख रूप से शामिल रहे।मंत्री ए.के. शर्मा ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक राहत दिखाई देनी चाहिए। जनता की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनसुनवाई कार्यक्रम शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से संभव हो पाता है और शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है।ऊर्जा विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, खराब ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन तथा विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, सीवर जाम, जलभराव, आवास योजनाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए।

लखनऊ में युवक को गोली लगने से सनसनी, पुराने विवाद में हुई वारदात की आशंका

लखनऊ। राजधानी के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात गोली चलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। विजयपुर के आगे किसान चबूतरा के पास एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार घायल युवक की पहचान मोनू शुक्ला उर्फ रोहित (25) निवासी रंजीतपुर सुनहरा, थाना मोहम्मदपुर खाला, बाराबंकी के रूप में हुई है, जो वर्तमान में चिनहट क्षेत्र में रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विभूतिखंड पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।घायल मोनू शुक्ला ने पुलिस को बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से उसका सैफ, शान यादव, अक्शीर, सार्थक यादव, डेविड, लकी यादव तथा दो अन्य लोगों के साथ विवाद और मारपीट चल रही थी।

भाजपा उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश टीम घोषित, संगठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने नए प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष से विचार-विमर्श के बाद नई टीम का ऐलान किया। नई टीम में संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है।घोषित सूची के अनुसार सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, बज बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और

आलोक गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।प्रदेश संगठन में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान, रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।पार्टी ने छहों क्षेत्रीय इकाइयों के अध्यक्षों की भी घोषणा की है। पश्चिम क्षेत्र की कमान नबाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र की पूरनलाल लोधी, कानपुर क्षेत्र की राम किशोर साहू, अवध क्षेत्र की अवधेश द्विवेदी, काशी क्षेत्र की अशोक चौरसिया और गोरखपुर क्षेत्र की विनोद राय को सौंपी गई है।मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी रोहित मिश्रा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रकाश पाल, किसान मोर्चा की देवेन्द्र सिंह, अनुसूचित मोर्चा की अशोक रावत, महिला मोर्चा की सरोज कुशवाह तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की विद्याभूषण गोंड को दी गई है।संगठन के मीडिया और कार्यालय प्रबंधन से जुड़े पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। भारत दीक्षित को कार्यालय मंत्री, अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह-मंत्री बनाया गया है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक तथा हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक वर्ष से फरार युवक गिरफ्तार

लखनऊ। कृष्णानगर थाना पुलिस ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के चर्चित मामले में करीब एक वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपना मोबाइल नंबर बदलकर दिल्ली में छिपकर नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उसे कासगंज जिले से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 19 जून 2025 को अलीगढ़ निवासी सत्यवान सिंह ने थाना कृष्णानगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री चंचल सिंह को सुभाष और उसके परिजन लगातार फोन पर अपशब्द कहकर प्रताड़ित करते थे तथा जान से मारने की धमकियां देते थे। इस मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर उनकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में थाना कृष्णानगर में मुकदमा संख्या 295/2025 धारा 108, 352 और 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया था।

बीबीएयू के प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा प्राकृतिक खेती में योगदान के लिए सम्मानित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर नवीन कुमार अरोड़ा को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पांच बार सांसद रहे अनुराग सिंह ठाकुर ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया। मानव विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती विषयक कार्यक्रम में प्रो. अरोड़ा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुराग सिंह ठाकुर ने की, जबकि पद्मश्री सम्मान से अलंकृत नेकराम शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा को बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुदृढ़ करने, किसानों को प्रकृति आधारित कृषि पद्धतियों से जोड़ने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने क्षेत्र में किसानों को टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ जैव उर्वरक उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है।इस उपलब्धि पर बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने प्रो. अरोड़ा को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है, बल्कि विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक समाज और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।प्रो. अरोड़ा ने बिलासपुर में जैव उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना कर किसानों को पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाली खेती की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इस पहल से स्थानीय किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद मिल रही है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती आधारित राज्य बनाना सामूहिक लक्ष्य है। इसके लिए किसानों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा जैसे वैज्ञानिकों का अनुभव और शोध किसानों की आय बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में स्थायी और समावेशी विकास को भी गति प्रदान करेंगे। प्राकृतिक खेती न केवल भूमि की उर्वरता बनाए रखती है बल्कि किसानों की लागत कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होती है।अपने संबोधन में प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

प्रदेश के किसानों और ग्रामीण गरीबों को बड़ी सौगात, चना-सरसों खरीद अवधि बढ़ी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महत्वपूर्ण स्वीकृति पत्र सौंपते हुए किसानों और ग्रामीण आवास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं।लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब किसान 24 जून से 8 जुलाई तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इस निर्णय से उन किसानों को विशेष लाभ मिलेगा जो पूर्व निर्धारित अवधि में अपनी उपज नहीं बेच पाए थे।केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 6 लाख 18 हजार नए आवासों की स्वीकृति दिए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे लाखों गरीब परिवारों का पक्का घर पाने का सपना पूरा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर बनेगा।

अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है तथा केंद्र सरकार प्रदेश को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की छोटी जोतों को अधिक लाभकारी बनाने के लिए समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना होगा, जिससे खेती के साथ पशुपालन, बागवानी और अन्य गतिविधियों को जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

जन्मदिन विशेष : आदर्शवादी राजनीति के पुरोधा : पहाड़ के विकास को 'मिशन' बनाने वाले डॉ. शिवानंद नौटियाल

भारतीय राजनीति के समकालीन इतिहास में ऐसे गिने-चुने ही राजनेता हुए हैं, जिन्हें उनके पद या कद से नहीं, बल्कि जन-सरोकारों से जुड़े उनके ऐतिहासिक कार्यों की वजह से याद किया जाता है। डॉ. शिवानंद नौटियाल सियासत के उसी ध्रुवतारे का नाम है, जिन्होंने राजनीति की पथरीली पिच पर आदर्शों और शुचिता का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित किया, जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। डॉ. नौटियाल महज़ सत्ता के गलियारों में जगह बनाने वाले नेता नहीं थे, उनकी आंखों में ढेरों सपने थे। लेकिन इन सपनों की तासीर अलग थी। ये सपने उन्होंने अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य के लिए नहीं, बल्कि समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए देखे थे, जिसकी तरफ़ बरसों से मुख्यधारा की राजनीति ने अपनी नजरें फेर रखी थीं। डॉ. शिवानंद नौटियाल इस बुनियादी सच को बख़ूबी समझते थे कि समाज का वास्तविक उत्थान केवल नारों से नहीं, बल्कि ज्ञान के उजाले से संभव है। यही वजह थी कि उन्होंने बच्चों की बुनियादी शिक्षा को अपने जीवन का मुख्य ध्येय बनाया। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र में, जहां अभावों की धुंध गहरी थी, वहां उन्होंने गरीब-गुरबों और वंचितों के हक की आवाज़ बुलंद की। बुनियादी ज़रूरतों रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ उन्होंने इस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया कि हर गरीब के बच्चे की पहुंच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक कैसे हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह इकलौती चाबी है, जो पीढ़ियों की ग़रीबी के ताले को खोल सकती है। आमतौर पर लोग राजनीति को शक्ति और प्रभाव के माध्यम के रूप में देखते हैं, लेकिन डॉ. नौटियाल के लिए राजनीति कोई व्यवसाय या शौक नहीं, बल्कि एक पवित्र मिशन थी। इसी वजह से उन्होंने जन-कल्याणकारी सपनों को धरातल पर उतारने के लिए, चुनावी राजनीति की देहरी पर कदम रखा था। समकालीन दौर में जहां जनप्रतिनिधि अक्सर चुनाव जीतने के बाद अपनी ही जनता से दूरी बना लेते हैं, वहीं डॉ. शिवानंद नौटियाल ने राजनीति में कदम ही इसलिए रखा था ताकि समाज के उस उपेक्षित वर्ग को मुख्यधारा में लाया जा सके, जिसके साथ आज भी व्यवस्था और समाज दो-रंगा बर्ताव करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि इच्छाशक्ति दृढ़ हो, तो राजनीति को लोक-कल्याण का सबसे सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। डॉ. शिवानंद नौटियाल का जन्म 26 जून 1926 को पौड़ी जनपद के ग्राम कोटला में हुआ था। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई।वर्ष 1967 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और दो वर्ष बाद, 1969 में पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होकर जनसेवा के नए अध्याय की शुरुआत की। सियासी रिकॉर्ड बनाते हुए पौड़ी से दो और कर्णप्रयाग से छह बार जीत का परचम ! फहराया डॉ. शिवानंद नौटियाल का जनता के बीच आधार कितना मजबूत था, इसकी गवाही उनके चुनावी आंकड़े देते हैं। उनकी इसी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता को देखते हुए साल 1979 में उन्हें उत्तर प्रदेश (संयुक्त) सरकार में उच्च शिक्षा एवं पर्वतीय विकास मंत्री की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। वे केवल एक कद्दावर राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक प्रखर बुद्धिजीवी और लेखक भी थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई कालजयी पुस्तकों की रचना कर साहित्य जगत में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी।

संघ, हिंदुत्व व सनातन पर सुनियोजित हमले

बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद संघ, हिंदू तथा सनातन विरोधी ताकतें पुनः पूरी आक्रामकता के साथ सक्रिय हो गयी हैं। जिन जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, उन-उन राज्यों संघ, हिंदुत्व व सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला कर्नाटक से आया जहां कांग्रेसी गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने संघ के पंजीकरण व फंडिग पर प्रश्न उठाते हुए, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने पर संध पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। केरल के नए-नवेले मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने केरल के तीन कुलपतियों द्वारा संघ के कार्यक्रम में भाग लेने पर घोर आपत्ति जताते हुए उन्हे नोटिस थमा दी है और तीनों कुलपतियों से माफी मांगने को कहा जा रहा है। इसी बीच सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने बयान दिया कि देश का बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है। जावेद अली ने कहा कि बीजेपी की वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ी है। धर्म के आधार पर लोगों का एक दूसरे पर भरोसा टूट गया है। उत्तर प्रदेश में बकरीद के अवसर पर दोस्ती के बहाने असद ने सूर्या को बुलाया और पूरे परिवार ने मिलकर उसकी नृशंस हत्या कर दी तब ये लोग चुप्पी बांधे सूर्या के हत्यारे असद के साथ खड़े हो गए। जब असद का एनकाउंटर हुआ था तब ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए असद के लिए फातिहा पढ़ रहे थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पुराना सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है। यदि केरल के तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने संघ की किसी व्याख्यान माला, बौद्धिक चर्चा या सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रोता के रूप में भाग ले लिया तो इसे अपराध या पद की गरिमा के विरुद्ध कैसे माना जा सकता है? इसके लिए उन्हें माफी मांगने को क्यों कहा जा रहा है? जब कुलपति वामपंथी विचारकों, गांधीवादी या अम्बेडकरवादी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं या अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उसे ₹बौद्धिक संवाद₹ कहा जाता है किन्तु यदि वही कुलपति संघ प्रमुख का व्याख्यान सुन ले तो उससे माफी मांगने को कहा जाता है। यह दोहरा मापदंड है।

विश्वविद्यालय ज्ञान, संवाद और विचार-विमर्श के केंद्र होते हैं, वैचारिक बहिष्कार के नहीं। यदि किसी कुलपति ने मंच से कोई राजनीतिक घोषणा नहीं की, किसी दल का प्रचार नहीं किया, किसी प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित नहीं किया, वरन मात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया, तो उसे ₹संघ कार्यकर्ता के स्तर तक गिर जाना₹ कहना उच्च शिक्षा संस्थानों और कुलपति की गरिमा का अपमान है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन विचारों से असहमति और व्यक्तियों के बहिष्कार में अंतर होता है। यदि संघ से वैचारिक मतभेद हैं, तो उसका उत्तर विचार से दिया जाना चाहिए, न कि लोगों को कार्यक्रम में जाने से रोककर प्रताड़ित करके। विडंबना यह है कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैचारिक बहुलता की बात करते हैं, वही आज यह तय करना चाहते हैं कि कुलपति किसका व्याख्यान सुन सकते हैं और किसका नहीं। क्या भारत में अब किसी शिक्षाविद् को कोई व्याख्यान सुनने के लिए राजनीतिक अनुमति लेनी होगी?

सर्वविदित है कि संघ सौ साल से काम कर रहा है। सब जानते हैं कि संघ क्या करता है। जो सोया है उसे जगाया जा सकता है जो सोने का नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता है। संघ की समाज में निश्चित छवि है। संघ अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं अपितु समाज के हित में काम करता है। आरोपों का उत्तर देने में संघ समय नहीं व्यर्थ करता है। संघ के स्वयंसेवक समाज में काम करते हैं। संघ बढ़ रहा है तो हर जगह दिख रहा है। संघ की छवि बिगाड़ने वालों का प्रयास करने वालों की अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। समाज के हर वर्ग के लोग संघ को प्रेम दे रहे हैं। संघ के काम को समाज आशीर्वाद देता है।

वर्तमान कांग्रेस जो आज संघ व भाजपा पर प्रतिबंध लगाने का सपना देख रही है उसको ध्यान रखना चाहिए कि यही काम नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और सोनिया जी तक करने का प्रयास करती रही हैं। प्रियांक जैसा दुस्साहस नेहरू जी ने किया था। वो अपने पत्रों में संघ को खतरा बताते थे और जिन्ना की मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देते थे। कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति मोहब्बत की यह दुकान केरल में केरल में आज भी चल रही है। केरल के सीएम नाराज हैं कि तीन कुलपति संघ के कार्यक्रम में चले गए थे। इसी प्रकार एक बार नेहरू जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन से नाराज हो गए थे क्योकि वह संघ की शाखा में चले गए थे। उस समय नेहरू जी के लिए संघ, पाकिस्तान से भी खतरनाक था। नेहरू तो गांधी की हत्या के पहले से ही संघ के खिलाफ योजना बना रहे थे। गाँधी की हत्या हुई तो अवसर मिल गया और प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन उसके विरुद्ध साबित कुछ नहीं हुआ। कांग्रेसी आज तक संघ को समाप्त करने का सपना देख रहे हैं और संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इनके नेताओं के मन में संघ, भाजपा व हिंदुत्व के प्रति जो घृणा है उसका मूल कारण यही है कि आज संघ व हिंदुत्व सर्वव्यापी हो चुका है।

भारत से शिकागो और फिर हुगली तक : स्वामी विवेकानंद के योग संदेश की वैश्विक यात्रा

रतापराव जाधव

योग के प्रारंभिक बीज ऋग्वेद (लगभग 1500–1200 ईसा पूर्व) में मिलते हैं, जहाँ तप और ध्यान जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलकर इन विचारों का विकास उपनिषदों में हुआ

समूचे इतिहास में, कुछ विचार सरहदों के पार जाकर समाजों को बदलते रहे हैं। योग भारत की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है, जिसकी यात्रा प्राचीन शास्त्रों से शुरू होकर वैश्विक मान्यता तक जा पहुँची है। से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकत्व स्थापित करना- अपने भीतर दार्शनिक चिंतन और व्यावहारिक अनुशासन की एक समग्र प्रणाली समाहित किए हुए है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति (जीवात्मा) का सार्वभौमिक चेतना (परमात्मा) के साथ मिलन कराना है।

योग के प्रारंभिक बीज ऋग्वेद (लगभग 1500–1200 ईसा पूर्व) में मिलते हैं, जहाँ तप और ध्यान जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलकर इन विचारों का विकास उपनिषदों में हुआ, जिन्होंने योग के अनेक दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। हालाँकि योग को उसका सर्वाधिक व्यवस्थित स्वरूप महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योगसूत्र (लगभग 200 ईसा पूर्व–400 ईस्वी) ने प्रदान किया- इसमें अष्टांग योग अथवा आठ अंगों वाले मार्ग का वर्णन किया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।

पतंजलि के अलावा, भगवद गीता योग को जीवन जीने के गतिशील दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है। कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र की पृष्ठभूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव कर्तव्य, उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति के विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवद्गीता में वर्णित विभिन्न मार्गों में कर्म योग (निःस्वार्थ कर्म का मार्ग), ज्ञान योग (ज्ञान का मार्ग) और भक्ति योग (भक्ति का मार्ग) मुक्ति प्राप्ति के तीन प्रमुख पथ माने गए हैं। अतः भारत केवल योग की जन्मभूमि ही नहीं है—यह एक जीवंत सभ्यता है, जहाँ योग सहस्राब्दियों से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, और जो इसकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक संरचना का अभिन्न अंग रहा है। हालाँकि, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय समाज के शिक्षित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी बौद्धिक विचारधाराओं से प्रभावित होने और योग सहित भारत की अनेक पारंपरिक ज्ञान-परंपराओं को बदलती आधुनिक दुनिया में अपेक्षाकृत कम प्रासंगिक माना जाने लगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में, स्वामी विवेकानंद एक सशक्त स्वर बनकर उभरे, जिन्होंने लोगों को योग के वास्तविक महत्व को फिर से जानने में मदद की।

स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों और विश्व धर्म संसद में दिए ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से दुनिया का ध्यान भारत की आध्यात्मिक विरासत की ओर आकृष्ट किया और योग की शाश्वत ज्ञान-परंपरा के प्रति लोगों में नया विश्वास जगाया। उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों के लोगों के साथ वेदांत और योग के सिद्धांत साझा किए तथा यह स्पष्ट किया कि योग केवल एक धार्मिक साधना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, आंतरिक शांति और आत्म-विकास का मार्ग भी है। विदेशों में स्वामी विवेकानंद को मिले व्यापक सम्मान और प्रशंसा ने भारतीयों के मन में अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के प्रति नया विश्वास और गौरव उत्पन्न किया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो - और उसके बाद अमेरिका भर में तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अपने व्याख्यानों के माध्यम से पश्चिमी जगत को राजयोग (मन के नियंत्रण का योग), ज्ञानयोग (विवेक और ज्ञान का मार्ग), कर्मयोग (निःस्वार्थ सेवा का मार्ग) तथा भक्तियोग (ईश्वर-प्रेम और समर्पण का मार्ग) से परिचित कराया। पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित उनकी पुस्तक राजयोग (1896), पश्चिमी समाज के लिए योग-दर्शन का परिचय कराने वाली प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभावशाली कृतियों में से एक बन गई।

राजयोग पर दिए अपने व्याख्यानों में स्वामी विवेकानंद ने योग को मानव चेतना के आंतरिक आयामों की खोज करने वाली एक व्यवस्थित और अनुभव-आधारित साधना के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानवता के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान उसकी आध्यात्मिक ज्ञान-परंपरा है, और योग उस परंपरा की सबसे गहन तथा स्थायी अभिव्यक्तियों में से एक है। उनके विचारों ने उस समय के जाने-माने बुद्धिजीवियों और विचारकों का ध्यान खींचा, जिससे भारतीय दर्शन के साथ पश्चिमी देशों का जुड़ाव और बढ़ा।

जो बात शायद कम चर्चित है— किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण है, — वह यह है कि पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद के कार्यों ने भारत के भीतर ही योग के पुनर्जागरण को प्रेरित किया। जब स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटे, तो वे खाली हाथ नहीं लौटे थे। वह अपने साथ एक नया आत्मविश्वास – भारत की आध्यात्मिक विरासत पर गर्व की एक नई भावना लाए थे – जो पश्चिम में उनके स्वागत से और बढ़ गई थी।

1897 में भारत लौटने के बाद, स्वामी विवेकानंद ने देशभर में व्याख्यान दिए और लोगों को भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को पुनः खोजने के लिए प्रेरित किया। 1 मई 1897 को, स्वामी विवेकानंद ने हावड़ा के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की — जो हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर है, उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर जहाँ रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में अपने आखिरी साल बिताए थे। बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित यह संस्थान एक आंदोलन का वैश्विक मुख्यालय बन गया, जिसने वेदांत के आदर्शों, सेवा को पूजा मानना (शिव ज्ञाने जीव सेवा) तथा योग-दर्शन के व्यावहारिक अनुप्रयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं की धरती होने के बावजूद, बदलते समय के साथ बंगाल में योग की सार्वजनिक दृश्यता धीरे-धीरे कम होती गई। जीवनशैली में परिवर्तन, आधुनिक प्राथमिकताओं के उभरने और सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण योग धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन के केंद्र से दूर होता गया। फिर भी, इसकी जड़ें आध्यात्मिक संस्थाओं और समर्पित साधकों के माध्यम से जीवित रहीं।

11 सितंबर 1893 को, अमेरिका के बहनों और भाइयों के अमर अभिवादन के साथ शुरुआत करते हुए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से दुनिया को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया। अब यह पंक्तियाँ पश्चिम बंगाल के बहनों और भाइयों, अपने ही घर में योग की घर वापसी के साक्षी बनिए- शिकागो के वैश्विक मंच से लेकर हुगली के तट तक - गहरे भावनात्मक संबंध को व्यक्त करती हैं, जो हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती हैं, जब स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया था। उनका संदेश भारत से विश्व तक पहुँचा और योग, सामंजस्य तथा आंतरिक शांति के मूल्यों का प्रसार करता गया। आज हुगली के तटों पर जो लौटा है, वह स्वयं योग नहीं है—क्योंकि भारत में योग कभी समाप्त ही नहीं हुआ—बल्कि योग के प्रति वह नवीनीकृत वैश्विक मान्यता और सराहना है, जिसकी शुरुआत भारत के प्राचीन ऋषियों से हुई और जिसे स्वामी विवेकानंद के संदेश ने विश्व मंच पर नए रूप में अभिव्यक्त किया।

टिप्पणी

खतरे की घंटी बजा

टीसीएस में मानव कर्मचारियों की संख्या आधी रह जाएगी। जो वहां होगा, वही रुझान अन्य आईटी कंपनियों में भी देखने को मिल सकता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री में फिलहाल 60 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं।

टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन दो टूक यह कह कर खतरे की घंटी बजा दी है कि उनकी कंपनी में अब जितने मानव कर्मचारी होंगे, उतनी ही संख्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) एजेंट लगाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मानव कर्मचारियों की संख्या अगले कुछ वर्षों में आधी रह जाएगी। जो टीसीएस में होगा, जाहिर है, वही रुझान अन्य आईटी कंपनियों में भी देखने को मिलेगा। भारत की आईटी इंडस्ट्री में फिलहाल 60 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इस क्षेत्र में तनख्वाह अपेक्षाकृत ज्यादातर अन्य क्षेत्रों से अधिक रही है।

इस रूप में ये उद्योग भारत में उपभोक्ता मध्य वर्ग का सबसे बड़ा सहारा है। आय कर दाताओं में सबसे बड़ा हिस्सा आईटी कर्मियों का ही है। अब अगर रोजगार के लिहाज से देखें, तो एआई इस क्षेत्र के लिए तलवार बन कर आई है। नए डिग्रीधारियों के लिए अवसर यहां पहले से सिकुड़ रहे हैं। पिछले साल कर्मचारियों की छंटनी भी जोर पकड़ गई। खुद टीसीएस से 12 हजार कर्मी निकाले गए। अब चंद्रशेखरन ने साफ किया है कि यह सब नीतिगत निर्णय के तहत हो रहा है। मतलब यह कि साल 2000 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री लेकर बेहतर करियर बना लेने का जो भरोसा भारत में बना, अब उसकी नींव हिलने लगी है।

नौकरियों की संभावना नहीं होगी, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के फैले जाल पर भी बुरा असर पड़ेगा। आशंका पहले से जताई जा रही है कि इन सबका असर मध्य वर्ग के सिकुड़ने के रूप में सामने आएगा। यानी आईटी इंडस्ट्री में जो होने जा रहा है, उसके परिणाम दूरगामी हैं। बेशक, एआई से नए कौशल वाली कुछ नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन ट्रेंड यह है कि एआई एजेंट दोहराव वाले हर ऐसे कार्य के लिए प्रशिक्षित होते जा रहे हैं, जिनमें तकनीकी कौशल की जरूरत पड़ती है। स्पष्टतः जितनी नौकरियां जाएंगी, उसकी तुलना में बहुत कम नए रोजगार पैदा होंगे। और यह तो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात है। एआई का उपयोग ऐसे अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जहां ह्वाइट कॉलर रोजगार के अवसर बनते रहे हैं। वहां भी तलवार गिरने वाली है।

ब्लॉग

अगर धमकी देते देते पाकिस्तान ने सचमुच युद्ध छेड़ दिया तो भारत क्या करेगा?

नीरज कुमार दुबे

बड़बोले ख्वाजा आसिफ कभी भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं, कभी जल युद्ध की हुंकार भरते हैं और कभी देशी विदेशी मीडिया को दिए गए साक्षात्कारों में यह कबूल करते नजर आते हैं कि हर जंग में पाकिस्तान की फौज को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ताजा गीदड़ भभकी भी उसी बौखलाहट का नतीजा है, जो आतंकवाद के सहारे भारत को अस्थिर करने की नाकाम कोशिशों के बाद अब पानी के मुद्दे पर नया शोर मचा रही है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों ही अपने ही देश की नाकामियों को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रहे हैं।

हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़भभकी दी है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो इस्लामाबाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पानी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अगर जल आपूर्ति रोकने की दिशा में आगे बढ़ता है तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया था कि आतंकवाद और बातचीत अब साथ-साथ नहीं चल सकते।

उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु बेसिन से मिलने वाले जल से पाकिस्तान की करीब अस्सी प्रतिशत खेती चलती है। लेकिन दशकों तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को अब इस बात का डर सताने लगा है कि संधि स्थगित होने के बाद भारत अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत अपने अधिकार के पानी का इस्तेमाल बढ़ाएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर संकट और गहराता जाएगा।

साथ ही ख्वाजा आसिफ ने भारत पर चिनाब नदी के प्रवाह को हथियार की तरह इस्तेमाल करने और जल संबंधी सूचनाएं रोकने का आरोप लगाया है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई नहरों में भारी जल कमी दर्ज की गई है, जबकि पंजाब प्रांत पर तय हिस्से से ज्यादा पानी लेने के आरोप लग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के प्रांतों के बीच पानी को लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी अपने ही घर में जल संकट और अव्यवस्था संभालने में नाकाम पाकिस्तान अब भारत पर आरोप लगाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है

लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि यह पुराना भारत नहीं है। पिछले महीने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया था कि भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और यदि जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तीनों सेनाएं चौबीसों घंटे तैयारी कर रही हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल मजबूत किया जा रहा है और भविष्य के युद्ध की हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। जनरल द्विवेदी का यह बयान भारत की सैन्य शक्ति और आत्मविश्वास का परिचायक था। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध का मैदान पूरी तरह पारदर्शी हो चुका है, जहां दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सजग है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब हर मोर्चे पर निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखता है। आतंकवाद, घुसपैठ, जल विवाद या सीमा पर उकसावे की हर हरकत का जवाब नए भारत की सेना उसी भाषा में देना जानती है। ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की कमजोरी और डर को उजागर करती हैं, जबकि भारतीय सेना का शौर्य, अनुशासन और तैयारी यह साबित करती है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस बार बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

भारत और पाक सैन्य क्षमता की तुलना देखिये

फिर भी यदि मान लिया जाए कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिमाकत करता है तो सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? इसका जवाब यह है कि इस बार भारत की ओर से केवल सीमा पर जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को ऐसी मार झेलनी पड़ सकती है जिसकी कल्पना भी इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने नहीं की होगी। भारतीय सेनाध्यक्ष के बयानों के अलावा, दुनिया भर की रक्षा रिपोर्टों और सैन्य विश्लेषणों का अध्ययन बताता है कि पारंपरिक युद्ध क्षमता, आधुनिक हथियारों, आर्थिक ताकत, सैन्य तकनीक और रणनीतिक तैयारी के मामले में भारत पाकिस्तान पर कई गुना भारी पड़ता है।

हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे अनुभवी और विशाल सेनाओं में शामिल भारतीय थलसेना के पास सैनिक संख्या, आधुनिक तोपखाना, मिसाइल शक्ति और युद्धक टैंकों का ऐसा जाल है जो पाकिस्तान की जमीनी रक्षा को चंद दिनों में चरमरा सकता है। भारत के पास पिनाका बहु नली रॉकेट प्रणाली, धनुष तोप, K9T अजय टैंक, T90 भीष्म टैंक और ब्रह्मोस जैसी घातक मारक क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। हाल के वर्षों में भारत ने स्वदेशी रक्षा निर्माण को तेजी से मजबूत किया है, जिसके कारण सेना को लगातार आधुनिक हथियार और तकनीक मिल रही है।

भारतीय सेना का सबसे बड़ा फायदा उसका वास्तविक युद्ध अनुभव और ऊंचे पर्वतीय इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना लंबे समय से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों से जूझ रही है। साथ ही भारत की रक्षा बजट क्षमता पाकिस्तान से कई गुना अधिक है, जिससे हथियारों की खरीद, तकनीकी उन्नयन और युद्ध तैयारी लगातार मजबूत होती जा रही है। साथ ही भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर है जबकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन और दूसरे देशों पर निर्भर है।

वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो यह वह ताकत है जो किसी भी आधुनिक युद्ध का रुख घंटों में बदल सकती है। भारतीय वायुसेना के पास रॉफेल, सुखोई तीस एमकेआई, तेजस और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। रॉफेल को दुनिया के सबसे खतरनाक बहुउद्देश्यीय युद्धक विमानों में गिना जाता है। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और अत्याधुनिक राडार प्रणाली पाकिस्तान के अधिकतर विमानों पर भारी पड़ सकती है। कई वैश्विक सैन्य अध्ययनों में माना गया है कि भारत की वायु शक्ति संख्या और तकनीक दोनों में पाकिस्तान से बहुत आगे है।

भारतीय वायुसेना की सबसे घातक ढाल एस-400 वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती है। हालिया सैन्य अभियानों और अभ्यासों में इस प्रणाली ने साबित किया कि पाकिस्तान की हवाई घुसपैठ या मिसाइल हमले को भारतीय रक्षा कवच के सामने टिकना बेहद कठिन होगा।

समंदर की बात करें तो भारतीय नौसेना पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता पर भारी बढ़त रखती है। भारत के पास विमानवाहक पोत विक्रांत, परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, अत्याधुनिक युद्धपोत, विध्वंसक जहाज और लंबी दूरी तक मार करने वाली समुद्री मिसाइलें हैं। भारतीय नौसेना अरब सागर में पाकिस्तान के बंदरगाहों और समुद्री आपूर्ति मार्गों को घेर सकती है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर है और यदि भारतीय नौसेना ने नाकेबंदी कर दी तो पाकिस्तान के लिए ईंधन, हथियार और व्यापारिक आपूर्ति बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

इसके अलावा, भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल हथियार नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के बीच बढ़ता तालमेल भी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत भविष्य के युद्ध के लिए चौबीसों घंटे तैयारी कर रहा है और तीनों सेनाएं मिलकर समन्वित युद्ध रणनीति पर काम कर रही हैं। आधुनिक निगरानी प्रणाली, सूचना युद्ध, उपग्रह क्षमता और त्वरित हमला करने की तैयारी भारत को निर्णायक बढ़त देती है।

हालांकि यह भी सच है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी पूर्ण युद्ध का परिणाम पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन पारंपरिक युद्ध क्षमता की बात करें तो वैश्विक रक्षा विश्लेषण साफ संकेत देते हैं कि भारत संख्या, तकनीक, अर्थव्यवस्था, हथियारों और रणनीतिक तैयारी के मामले में पाकिस्तान पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ता है। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकियां तो देता है, लेकिन सीधे युद्ध की कीमत चुकाने का साहस शायद ही जुटा पाए।

बहरहाल, सैन्य ताकत के साथ-साथ भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णायक नेतृत्व भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के सामने एक ऐसे सख्त और स्पष्ट नेता की छवि बनाई है जो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े वैश्विक अभियान तक, मोदी ने यह साबित किया है कि नया भारत केवल चेतावनी नहीं देता बल्कि जवाब भी देता है। आज दुनिया के प्रमुख देशों के साथ भारत के मजबूत रणनीतिक संबंध हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मोदी की बात को गंभीरता से सुना जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की स्थिति अपने ही देश में कमजोर और विवादों से घिरी हुई है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की छाया से जूझते पाकिस्तान के नेतृत्व की तुलना भारत के मजबूत और आत्मविश्वासी नेतृत्व से नहीं की जा सकती। यही कारण है कि जब भारत का नेतृत्व दृढ संकल्प के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान की धमकियां दुनिया को खोखली और बौखलाहट भरी ही नजर आती हैं।

पिता उदय प्रताप के साथ राजा भैया हाउस अरेस्ट, शांति व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने किया नजरबंद

आर्यावर्त संवाददाता

प्रतापगढ़। जिला प्रशासन ने मोहर्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह व 13 समर्थकों के साथ हाउस अरेस्ट (नजरबंद) किया है। यह एहतियाती कदम भदरी कोठी के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ उठाया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो कुंडा के शेखपुर में वर्ष 2012 में एक बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक हनुमान मंदिर का निर्माण किया था। राजा उदय प्रताप सिंह इसी मंदिर में हर वर्ष मोहर्रम के दिन

हनुमान पाठ और भंडारे का आयोजन करते हैं। तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाउस अरेस्ट की कार्रवाई की है। वर्ष 2013-14 में जुलूस और भंडारा साथ आयोजित होने पर स्थिति बिगड़ गई थी।

राजा भैया के आवास के बाहर पुलिस ने हाउस अरेस्ट की नोटिस चस्पा की है। समर्थकों में निर्भय सिंह बेंती, जुगनू विश्वकर्मा हथिगवां, हनुमान पांडेय कुंडा, जीतेंद्र यादव, आनंद पाल, रमाकांत मिश्रा, भवानी विश्वकर्मा, रवि सिंह, केशरी नंदन पांडेय, जमुना प्रसाद मौर्य, गया प्रयास प्रजापति, मोहन हथिगवां शामिल हैं। सीओ कुंडा शिव नारायण वैस ने बताया कि हाउस अरेस्ट किए गए लोगों के घर पर नोटिस चस्पा कर दी गई। पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। शुक्रवार की रात नौ बजे हाउस अरेस्ट की कार्रवाई जारी रहेगी।

बहजोई की राइस मिल में हादसा, 15 फीट गहरे चैंबर में उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस से मौत

आर्यावर्त संवाददाता

बहजाई। संभल के बहजोई क्षेत्र स्थित राइस मिल में बृहस्पतिवार को बड़ा हादसा हो गया। मक्का सुखाने वाले एलीवेटर के करीब 15 फीट गहरे चैंबर में उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद मिल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मजदूरों के शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

सेतु निर्माण का डीएम ने किया निरीक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के द्वारा जफराबाद-सुल्तानपुर- लखनऊ रेल सेक्शन पर के जौनपुर (सिटी यार्ड) उत्तर रेलवे के रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सेतु निगम की भौतिक प्रगति संतोषजनक पाई निर्देश दिया कि निर्माण के दौरान नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सेतु निर्माण इकाई, जौनपुर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य हेतु कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हुए सुरक्षा मानकों का अनुपालन एवं ध्यान देते हुए तीव्रगति से निर्धारित लक्षित समयावधि (माह जून, 2027) में गुणवत्तापूर्ण कार्य को सम्पादित कराया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि यह रेल उपरिगामी सेतु पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी तथा आवागमन अधिक सुगम एवं सुरक्षित होगा। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकरारा को उच्चीकृत कर 100 शैयायुक्त चिकित्सालय के रूप में विकसित किए जा रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा की। इस दौरान निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति अपेक्षाकृत धीमी तथा गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

3 जुलाई से होगा आम महोत्सव

जौनपुर। जिला उद्यान अधिकारी डॉ0 सीमा सिंह राणा ने अवगत कराया कि 3, 4 एवं 5 जुलाई, को इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। आम महोत्सव के माध्यम से किसानो, निर्यातको, उद्यमियो एंव उपभोक्ताओ को एक मंच पर लाकर आम उत्पादन प्रसंस्करण विपणन एंव निर्यात को नई गति देने का प्रयास किया जायेगा। बताया गया कि उ0प्र0 देश का अग्रणी आम उत्पादक राज्य है, महोत्सव के दौरान पाँच श्रेणियों में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी, जिनमें आम की विभिन्न प्रजातियाँ, आम आधारित संरक्षित उत्पाद, आम से बने व्यंजन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी तथा सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाले बागवान शामिल हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं आम उत्पादकों को उन्नत उत्पादन तकनीक, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट), प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन तथा निर्यात संबंधी आधुनिक जानकारियाँ उपलब्ध कराना है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद : कागभुसुंडी की भी प्रतिमा गायब होने के आरोप पर सेवादार ने बनाया वीडियो

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़े विवादों के बीच कागभुसुंडी जी की चांदी की प्रतिमा को लेकर लगाए गए आरोपों पर नया मोड़ आ गया है। कारसेवकपुरम के एक सेवादार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह दावा कर रहा है कि कागभुसुंडी चांदी की जिस प्रतिमा को लेकर चोरी या गायब होने के आरोप लगाए गए थे, उसकी आज भी कारसेवकपुरम में नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जाती है।

वीडियो में सेवादार प्रतिमा को दिखाते हुए कह रहा है कि कागभुसुंडी जी सुरक्षित हैं। प्रतिदिन विधि-विधान से उनकी पूजा होती है। उसका कहना है कि बिना पूरी जानकारी और सत्यता जाने कुछ लोगों ने अनावश्यक आरोप लगा दिए। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

सेवादार ने वीडियो में यह भी कहा कि दान का वास्तविक फल श्रद्धा और समर्पण में निहित होता है। उसके अनुसार, जिस महिला ने प्रतिमा दान की थी, उसने बाद में यह सवाल उठाया कि उसकी दी हुई प्रतिमा कहां है? सेवादार का दावा है कि दान करने के बाद यदि व्यक्ति बार-बार अपने दान का हिसाब मांगता है तो दान का आध्यात्मिक महत्व प्रभावित होता है। हालांकि, यह उसका व्यक्तिगत धार्मिक दृष्टिकोण है।

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व एक महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा दान की गई चांदी की कागभुसुंडी प्रतिमा का कोई पता नहीं है। आरोप सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। अब वायरल वीडियो के जरिए प्रतिमा के करसेवकपुरम में सुरक्षित होने और नियमित पूजा होने का दावा किया जा रहा है।

देहव्यापार के कथित अड्डे पर छापा, कई हिरासत में

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारी स्टेशन के समीप वाजिदपुर उत्तरी चमारी वीर बाबा रोड पर गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कथित देहव्यापार के अड्डे पर छापेमारी की। अचानक हुई इस कार्रवाई से हडकंप की स्थिति बन गई। सहायक पुलिस अधीक्षकध्क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता तथा सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके पर गहन जांच-पडताल की। कार्रवाई के दौरान कई महिला एवं पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। उक्त स्थान पर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों के संचालन की शिकायतें स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को दी जा रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया।अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा मौके से मिले तथ्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर इकाई द्वारा आज जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद् और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को श्बलिदान दिवसश के रूप में बेहद श्रद्धापूर्वक मनाया गया इस अवसर पर पार्टी के मुख्य कार्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चैरसिया और जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चैरसियाने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए समर्पित था उन्होंने

कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में कश्मीर से धारा ३७० को सदैव के लिए समाप्त कर डॉ. मुखर्जी के उस अधूरे सपने को पूरा किया गया है, जो हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गौरव का क्षण है।जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ. मुखर्जी का बलिदान हमें देश सेवा की निरंतर प्रेरणा देता है। आज श्बलिदान दिवसश से लेकर आगामी ६ जुलाई डॉ. मुखर्जी की जयंती तक पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हर बूथ पर कार्यकर्ता पौधे लगाएंगे।

गर्भवती महिला की मौत, लापरवाही का आरोप

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में 6 माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद क्षेत्र में हडकंप मच गया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला को उपचार के लिए खुटहन क्षेत्र के किरण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और उचित उपचार न मिलने के कारण गर्भवती महिला की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल संचालक समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

देशहित पर पीएम को लिखे पत्र पर आया पीएमओ का जवाब, युवा आशुतोष यादव की हुई सराहना

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। वैश्विक परिस्थितियों और देशहित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले बिल्हौर क्षेत्र के युवा पंचायत सहायक आशुतोष यादव को प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में उनके विचारों, जागरूकता और राष्ट्रहित के प्रति सकारात्मक सोच की सराहना की गई है।

बिल्हौर तहसील क्षेत्र के आराजी ईशेपुर (ढुलमऊ) गांव निवासी 25 वर्षीय आशुतोष यादव ने मई माह में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया था। साथ ही देशहित में आवश्यक होने पर कठिनाइयों और अभावों को स्वीकार करने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प भी जताया था। यह पत्र

दैनिक जागरण में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था।

अब प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त जवाबी पत्र में प्रधानमंत्री ने आशुतोष यादव के विचार साझा करने के लिए आभार व्यक्त किया है। पत्र में कहा गया है कि देशवासियों से मिलने वाले आत्मीय संदेश उन्हें राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनभागीदारी और आवश्यक वस्तुओं के विवेकपूर्ण उपयोग के उनके संकल्प को सराहनीय बताया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना तथा सामूहिक प्रयासों और जनशक्ति के बल पर देश अनेक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं वैश्विक विषयों के प्रति आशुतोष की जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र मिलने पर आशुतोष यादव ने इसे अपने लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया यह पत्र उन्हें राष्ट्रहित में कार्य करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाने की प्रेरणा देगा।

वाराणसी से हरिद्वार तक उमड़े श्रद्धालु, धर्मनगरीयों में दिखा उत्साह और भक्ति का संगम

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। निर्जला एकादशी के अवसर पर वाराणसी, हरिद्वार और मथुरा में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और पवित्र घाटों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना कर व्रत रखा और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और शोभायात्राओं का आयोजन किया गया। पवित्र नगरीयों के मंदिरों और घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने आस्था और उत्सव का अनूठा संगम प्रस्तुत किया।

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। महिलाएं अखंड सौभाग्य, परिवार की सुख-

समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना कर रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत वर्ष की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्रदान करने वाला माना जाता है।

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, शास्त्रों में निर्जला एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु इस दिन बिना जल ग्रहण किए साधना और उपवास करता है तो उसे पूरे वर्ष की समस्त एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।

महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। इस व्रत में सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक लगभग 24 घंटे जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं या डायबिटीज से पीड़ित लोगों को निर्जल व्रत न रखने की सलाह दी जाती है।

इस वर्ष निर्जला एकादशी विशेष शुभ संयोग में पड़ रही है। एकादशी तिथि 24 जून की शाम 6:12 बजे प्रारंभ हुई और 25 जून की रात 8:09 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 25 जून को निर्जला एकादशी महाव्रत रखा जा रहा है।

निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि यह व्रत जीवन में सुख-समृद्धि, सफलता, भाग्य वृद्धि और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है।

शास्त्रों में इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इसमें पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इसे आत्मसंयम, श्रद्धा और तपस्या की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यह व्रत करता है, उस पर भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं।

आठवीं मोहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस निकला

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। आठवीं मोहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस नाजिम अली खान के इमामबाडे से अंजुमन हुसैनिया के नेतृत्व में निकाला गया। इस अवसर पर मजलिस का भी आयोजन हुआ, जिसे दिल्ली से आए मशहूर वैज्ञानिक और जाकिर डॉ. कल्बे रजा नकवी ने संबोधित किया। जनपद के शहरी और ग्रामीण सभी इलाकों में मजलिसों और जुलूसों का आयोजन किया गया। शहर की 20 से अधिक मातमी अंजुमनों ने जुलूस में नौहा और मातम कर कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह जुलूस मोहल्ला नसीब खां मंडी स्थित इमामबाडा नाजिम अली खां से शुरू होकर अटाला मस्जिद स्थित इमामबाडा शेख अलताफ हुसैन पहुंचा। यहां शबीहे ताबूत को दुलदुल से मिलाया गया, जिसके बाद जुलूस वापस पहुंचकर समाप्त हुआ। डॉ. कल्बे

रजा नकवी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है इमाम हुसैन ने सन 61 हजिरी में कर्बला के मैदान में तत्कालीन सबसे बड़े आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई उनका बलिदान आज इस्लाम के अस्तित्व का आधार है। उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन ने अपने छह माह के बच्चे जनाबे अली असगर, जवान बेटे अली अकबर और तेरह साल के भतीजे जनाबे कासिम की शहादत दीने इस्लाम को बचाने के लिए पेश की।उन्होंने यजीदी हुकूमत के जुल्मों की इंतहा बताते हुए कहा कि छोटे बच्चों को भी पानी पीने से रोका गया था। इमाम हुसैन ने जंग के दौरान हजारों यजीदी फौजों को हलाक किया तभी आकाशवाणी हुई कि ऐ नफ्से मुतमइना पलट आ अपने रब की तरफ मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी। ये आकाशवाणी सुनकर जैसे ही इमाम हुसैन ने तलवार को अपनी मियान में रखा यजीदी फौजों ने उन्हें घेर कर हमला किया और शहीद कर दिया। जिसके बाद अंजुमन हुसैनिया बलुआघाट के नेतृत्व में शबीहे अलम जुलजनाह और गहवारे अली असगर बरामद हुआ।

10 रुपये की ये छोटी सी चीज है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, एक्सपर्ट ने गिनाए फायदे

अगर आपकी पाचन क्रिया कमजोर है, या आपको बदलते मौसम के साथ जल्दी जुकाम या खांसी हो जाता है तो ये कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। बडे.हो या बच्चे भारत की बड़ी आबादी कमजोर इम्यूनिटी का शिकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आयुर्वेदिक तरीके भी बहुत काम आते हैं। जब मॉडर्न दवाओं का चलन नहीं था तब हल्दी या दूसरी देसी चीजों से छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर ली जाती थी। वैसे आज के समय में लोग पुराने तरीकों को फिर से अपनाने लगते हैं। आयुर्वेद में काली मिर्च का भी महत्व बताया गया है।

आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ। चंचल शर्मा बताती हैं कि इसमें 'पाइपेरिन' नामक एंटीऑक्सीडेंट औषधि की तरह काम करता हैं। आपके खाने में डाले जाने वाली काली मिर्च आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से प्रभावित करती है। जानें ये कैसे करती है काम...

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

डॉ। चंचल शर्मा कहती हैं कि काली मिर्च के जरिए वात पित्त और कफ के दोषों को नेचुरल तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। इसमें संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। एनसीबीआई की रिसर्च में भी बताया गया है कि काली मिर्च विटामिन सी का एक बड़ा सोर्स है। इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बेहद कारगर है। एक्सपर्ट कहती हैं कि इसके गुण आपके शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं और आपको बीमारियों से भी दूर रखते हैं। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मौसम के अनुकूल ही इन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, सर्दी में हल्की ज्यादा मात्रा का सेवन नुकसान नहीं देगा परंतु गर्मी में ज्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है। इसलिए काली मिर्च का प्रयोग सीमित मात्रा में करें और स्वस्थ रहें।

काली मिर्च के कुछ औषधीय गुण

मज़बूत पाचनः इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके पेट को साफ एवं पाचन को तेज करने में मदद करते हैं।

वात, पित्त और कफ का संतुलनः काली मिर्च अपनी गर्म तासीर के कारण वात और कफ को तो शांत करती है।

लिवर को स्वस्थ रखनाः यह लिवर से हानिकारक पदार्थों (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे वह सुचारू रूप से और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाता है।

पेट के कीड़े हटाने का एंटीडोटः आयुर्वेद में काली मिर्च को एक बेहतरीन 'कृमिनाशक' औषधि माना गया है, जिसके कारण यह पेट के कीड़ों को नष्ट कर देती है।

अस्थमा के रोग में कारगरः अपनी गर्म तासीर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण यह छाती में जमे कफ को बाहर निकालती है, जिससे अस्थमा, पुरानी खांसी और सांस लेने की तकलीफ में बहुत आराम मिलता है।

क्या गर्मियों में काली मिर्च का उपयोग करना सही है?

एक्सपर्ट कहती हैं कि काली मिर्च की तासीर गरम होती है जिसके कारण ये शरीर में गर्मी पैदा करती है इसलिए काली मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में करना ही फायदेमंद है। अपने भोजन में काली मिर्च का 1 या 2 चुटकी की मात्रा का ही उपयोग करें।

काली मिर्च का ज्यादा सेवन करने के नुकसान

काली मिर्च एक आयुर्वेदिक औषधि है इसका सही मात्रा में सेवन आपको सेहतमंद रख सकता है परंतु इसका ज्यादा सेवन आपके शरीर पर उल्टा असर भी कर सकता है। शरीर में गर्मी का बढ़नाः इसकी तासीर गर्म होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है। पेट में जलनः संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोगों या अल्सर के मरीजों में यह सीने में जलन और पेट में दर्द का कारण बन सकती है। त्वचा की समस्याः ज्यादा काली मिर्च के सेवन से चेहरे पर दाने, फुंसियां या मुहांसे हो सकते हैं।

वर्क फ्रॉम होम में एक ही जगह रहकर बढ़ गया है स्ट्रेस

वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अब काफी बढ़ा है, कुछ दिनों पहले पीएम की अपील के बाद भी बहुत सारी कंपनियों ने WFH शुरू किया। ये कर्मचारियों के लिए आरामदायक लगता है, लेकिन एक ही जगह पर रहकर काम करने की वजह से कई बार स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसे में मूड को फ्रेश रखने के लिए कुछ आसान से तरीकों को फॉलो करें।

वर्क फ्रॉम होम में आपको ऑफिस जाने और आने का झंझट नहीं करना होता है, इसलिए कुछ टाइम बच जाता है। हालांकि घर से काम करना भी आसान नहीं होता है। इस दौरान लगातार अवेलेबल रहना, ऑनलाइन मीटिंग्स, चैट और मैसेजिंग, ईमेल के रिप्लाई का प्रेशर। इसी के साथ कलीग्स के साथ आमने-सामने से बातचीत न होने की वजह से काम का ज्यादा दबाव महसूस होता है। जब घर ही ऑफिस बन जाए तो फैमिली के बीच काम करने की वजह से काम का टाइम भी थोड़ा ज्यादा खिंच जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाली एंग्जायटी, स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हैं।

क्या आप भी अगर घर से काम कर रहे हैं? इस वजह से कभी-कभी बहुत हैवी फील करने लगते हैं तो मिनटों में आप इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके लिए अपने काम की जगह का ध्यान रखने से लेकर हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग जैसी कुछ चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है।

अलग बनाएं वर्क स्पेस

वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर काम न करें। इससे आपके काम में देरी होती है। जरूरी है कि आप अपने लिए घर में कोई ऐसी जगह को वर्कप्लेस बनाएं जहां पर शोर न होता हो और आप एकाग्र होकर काम कर पाएं। इससे आप ऑफिस की तरह ही अपनी तय की गई शिफ्ट में काम कंप्लीट कर पाएंगे और स्ट्रेस कम होगा।

बीच-बीच में लें ब्रेक

लगातार काम में लगे रहने की वजह से भी एंग्जायटी फील होने लगती है। ऑफिस की तरह ही बीच-बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेते रहें। इस दौरान थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे स्ट्रेचिंग करना, हल्का-फुल्का टहलना और अगर कॉल टॉक करनी हो तो भी वॉक करते हुए ही करें। कलीग्स- दोस्तों के साथ कैजुअल टॉक से जुड़े रहें। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा।

सुबह की शुरुआत करें धीमी

अब जबकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑफिस जाने की जल्दी नहीं रहती है। आपको बिल्कुल तय समय पर इन करना होता है तो ऐसे में सुबह की शुरुआत भागदौड़ भरी करने की बजाय हल्की करें। जैसे उठने के बाद कुछ देर चुपचाप रहें, हल्की खुली हवा में रहें और 3-4 मिनट गहरी सांसें लें। हल्की वॉक करें। इसके बाद कुछ योगासन करें और 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं। हल्का लेकिन पौष्टिक ब्रेकफास्ट करें। इससे आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलेगी और आप सुस्त महसूस नहीं करेंगे।

काम के बाद नोटिफिकेशन से दूरी

जब आपके ऑफिस का टाइम खत्म हो जाए तो उसके बाद ईमेल-मैसेज, नोटिफिकेशन से दूरी बना लें। वरना इस वजह से बिना बात ही आप अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं। ऑफिस का टाइम तय करें कि लॉग इन और लॉग आउट के बाद कोई एक्स्ट्रा काम अपने लिए बाकी न रखें।

वीकेंड का सही यूज

अपने वीकेंड के दौरान भी ये तय रखें कि कोई ईमेल, चैट, नोटिफिकेशन आपको स्ट्रेस न बढ़ाए। इसे बिल्कुल सीमित रखें। आप जब वीकेंड अच्छे से गुजारेंगे तभी हफ्ते भर के काम के लिए खुद को एनर्जेटिक बना पाएंगे। सुबह सैर करने जाएं। साइकिलिंग करने। प्रकृति के बीच टाइम बिताएं। ये 30-40 मिनट की एक्टिविटी भी आपके मूड को बेहतर बनाती हैं। अपने मी टाइम को पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी होता है।

मेकअप के लिए जरूरी हैं ये 5 टूल्स, हर महिला की किट में होने चाहिए शामिल

मेकअप करने के लिए सिर्फ सही सामान का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से लगाने के लिए सही टूल्स का होना भी जरूरी है, खासकर अगर आप मेकअप के लिए नए हैं तो आपको यह समझना होगा कि कौन सा टूल कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे मेकअप टूल्स के बारे में बताते हैं, जो हर महिला के पास होने चाहिए।

मेकअप ब्रश सेट

मेकअप ब्रश सेट आपके चेहरे पर सामान को सही तरीके से लगाने में मदद करता है। इसमें फाउंडेशन, गालों पर रंग, आंखों के लिए शेड और होंठों के लिए अलग-अलग ब्रश होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं। सही ब्रश का चयन और उपयोग आपके लुक को निखारने में अहम भूमिका निभाता है। अच्छे मेकअप ब्रश सेट से आप आसानी से और प्रभावी ढंग से मेकअप कर सकते हैं।

ब्लेंडर

ब्लेंडर एक ऐसा टूल है, जो फाउंडेशन और कंसीलर को चेहरे पर समान रूप से फैलाने में मदद करता है। इससे आपका मेकअप न केवल प्राकृतिक दिखता है बल्कि लंबे समय तक टिकता भी है।
ब्लेंडर का सही उपयोग करने से आपका चेहरा तरोताजा और निखरा हुआ लगेगा। इसे गीला करके इस्तेमाल करने से यह त्वचा में बेहतर समाहित होता है और एक स्मूद फिनिश देता है, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक बनता है।

आईलैश कर्लर

आईलैश कर्लर आपकी पलकों को घुमावदार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखती हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बस इसे अपनी पलक पर हल्के हाथों से दबाएं और झपकाएं। आईलैश कर्लर का सही उपयोग करने से आपकी आंखें खुली और जागती हुई दिखती हैं, जिससे आपका पूरा लुक और भी खास बनता है। यह टूल आपके मेकअप रूटीन का एक अहम हिस्सा हो सकता है।

आईब्रो पेंसिल

आईब्रो पेंसिल का उपयोग करके आप अपनी भौहों को आकार दे सकते हैं और उन्हें भर सकते हैं। सही आईब्रो आकार आपके चेहरे को फ्रेम करता है और आपकी आंखों को और भी आकर्षक बनाता है। आईब्रो पेंसिल का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह आपकी बालों के रंग से मेल खाती हो ताकि आपका लुक प्राकृतिक लगे। इसे हल्के हाथों से लगाएं और जरूरत पड़ने पर ब्रश की मदद से नरम करें।

होंठों के लिए ब्रश

होंठों के लिए ब्रश का उपयोग करके आप अपने होंठों पर लिपस्टिक या लिप ग्लॉस लगाते समय सटीकता प्राप्त कर सकते हैं। यह टूल खासकर तब उपयोगी होता है जब आप गहरे रंग की लिपस्टिक लगा रहे हों क्योंकि इससे आपको होंठों की सीमाएं साफ दिखती हैं। होंठों के लिए ब्रश का सही उपयोग करके आपके होंठ लंबे समय तक खूबसूरत बने रहते हैं और आपका पूरा लुक और भी खास बनता है।

हर वक्त फैसले लेना थका देता है, मीरा राजपूत ने महिलाओं के मानसिक सुकून पर कही दिल की बात

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं। ऐसे में मानसिक थकान और दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। इसी विषय पर बात करते हुए मीरा राजपूत कपूर ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि महिलाओं को कभी-कभी हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी और फैसलों से दूर होकर खुद के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि वे मानसिक रूप से हल्का महसूस कर सकें। मीरा राजपूत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने मायके में बिताए समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, अपने माता-पिता के घर पर रहना एक अलग तरह का सुकून देता है। मायके में मैं खुद को ज्यादा सहज महसूस करती हूं। यहां मुझे किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होता। वीडियो में मीरा आगे कहती हैं, काफी समय बाद मैं इस तरह खुलकर अपने मन की बात साझा कर रही हूं। जब मैं अपनी मां के घर पर थी, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगहें और रिश्ते ऐसे होते हैं, जो हमें बिना किसी शर्त के सुकून देते हैं। इस अनुभव को शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है।

मीरा ने कहा, महिलाओं को हर समय फैसले लेने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दिनभर उन्हें यह तय करना होता है कि घर में क्या बनेगा, कौन कहां जाएगा, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से थका देती है। जब कुछ समय के लिए कोई उनसे कुछ नहीं पूछता, तो दिमाग को बहुत राहत मिलती है।

उन्होंने आगे कहा, महिलाएं सिर्फ फैसले ही नहीं लेतीं, बल्कि हर दिन कई विकल्पों में से सही चुनाव भी करती हैं। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और इसका असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है। जब किसी महिला को कुछ समय के लिए इन सभी फैसलों और जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलता है, तो उसे एक अलग ही तरह की शांति और सुकून महसूस होता है। यही वह समय होता है, जब वह खुद को फिर से ऊर्जा से भर पाती है।

मीरा ने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा, समय-समय पर खुद को ब्रेक देना बहुत जरूरी है। अगर संभव हो, तो कुछ समय के लिए फोन बंद कर देना चाहिए और सिर्फ उस पल को जीने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से मन हल्का होता है और हम अपने आसपास की चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं।

उन्होंने कहा, जीवन के छोटे-छोटे पल ही असली खुशी देते हैं। जैसे बच्चों को खेलते हुए देखना, माता-पिता के साथ बिना किसी काम के समय बिताना, उनके साथ टहलना या हंसना, ये सभी चीजें हमें अंदर से खुश करती हैं। जब हम इन पलों को बिना किसी चिंता के जीते हैं, तब हमें असली सुकून मिलता है।

वीडियो के आखिर में मीरा राजपूत ने कहा, महिलाएं अपने लिए ऐसी जगह, इंसान या माहौल जरूर ढूंढें, जहां उन्हें किसी तरह का दबाव महसूस न हो और जहां उन्हें फैसले लेने की जरूरत न पड़े। कभी-कभी खुद से कोई सवाल न पूछना और बस उस पल में जीना भी बहुत जरूरी होता है।

कच्चा तेल बना रुपए का जिगरी दोस्त! करेंसी मार्केट में डॉलर को दिया करारा जवाब

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 .30 पर खुला और मजबूत होकर 94 .24 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे ज्यादा है। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 94 .55 पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि रुपए में दो दिनों में 52 पैसे की तेजी देखने को मिल चुकी है।

करीब चार महीनों के बाद रुपए का जिगरी दोस्त बाजार में वापस आ गया है। ये दोस्त कोई और नहीं सस्ता कच्चा तेल है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को खाड़ी देशों का कच्चा तेल प्री वॉर लेवल पर आ गया है। जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ते कदम भी रुपए को गिराने में नाकामयाब साबित हुआ है। सस्ते कच्चे तेल की बदौलत ही लगातार दूसरे दिन रुपए की शानदार शुरुआत हुई है। जबकि एक दिन पहले रुपए का अंत भी काफी अच्छा रहा था। तब से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए में 50 पैसे से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डॉलर के मुकाबले में रुपए में किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं।

लगातार दूसरे दिन रुपए में तेजी

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे बढ़कर 94.24 पर पहुंच गया। इसकी वजह ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट थी, जिससे कीमतें पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले के स्तर से भी नीचे आ गईं। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि डॉलर के कमजोर होने और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल ने रुपये को सहारा दिया, जबकि FII (विदेशी संस्थागत निवेशकों) की भारी बिकवाली ने इसमें और ज्यादा बढ़त को रोक दिया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.30 पर खुला और मजबूत होकर 94.24 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे ज्यादा है। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 94.55 पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि रुपए में दो दिनों में 52 पैसे की तेजी देखने को मिल चुकी है।

सस्ता कच्चा तेल बना रुपए का सहारा

चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी फंडामेंटल एनालिस्ट पिंकी यादव ने कहा कि ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 ।30 पर मजबूत खुला। कीमतें ईरान संघर्ष से पहले के स्तर से भी नीचे आ गईं। इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड में 10 प्रतिशत से ज्यादा और इस महीने 21 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे भारत के इंपोर्ट बिल को लेकर चिंता कम हुई है और घरेलू करेंसी को सहारा मिला है। यादव ने कहा कि हालांकि, रुपये में बढ़त सीमित रही क्योंकि अमेरिकी डॉलर 101.5 के आसपास एक साल के उच्चतम स्तर के करीब बना रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाए रख सकता है।

कुछ ऐसा है बाजार का हाल

इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी की बास्केट के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापता है, 101.50 पर ट्रेड कर रहा था, जो 0.10 प्रतिशत कम था। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड में 1.72 प्रतिशत गिरकर 72.47 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 440.23 अंक चढ़कर 77,435.76 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 137.80 अंक बढ़कर 24,147.60 पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को नेट आधार पर 1,843.40 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

ITR में नहीं बताई विदेशी कमाई या बैंक खाते की डिटेल, तो लगेगा ₹10 लाख का भारी जुर्माना!

नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में अक्सर लोग भारत से बाहर जाते हैं। कुछ सालों तक विदेश में काम करने के बाद जब वे स्वदेश लौटते हैं, तो उनकी एक आर्थिक दुनिया वहां भी बस चुकी होती है। वहां खरीदे गए घर, विदेशी बैंक अकाउंट या फिर किसी विदेशी कंपनी के शेयर, ये सभी आपकी कुल संपत्ति का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय इन विदेशी संपत्तियों की जानकारी छिपाना आपको बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर किसी भी भारतीय टैक्सपेयर की विदेश में कोई संपत्ति या आय है, तो उसे अपने रिटर्न में इसकी पूरी-पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर ब्लैक मनी कानून के तहत 10 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।

विदेश की कमाई छिपाना अब नामुमकिन

आज के डिजिटल और कनेक्टेड युग में टैक्स चोरी करना या अपनी संपत्ति छिपाना लगभग असंभव हो गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारतीय आयकर विभाग की नजर अब देश के साथ-साथ विदेशों में मौजूद आपकी संपत्तियों पर भी है। दरअसल, भारत सरकार का दुनिया के कई देशों के साथ सीधा सूचना समझौता है। इसके तहत विदेशी सरकारें और वहां के वित्तीय संस्थान सीधे तौर पर भारतीय आयकर विभाग के साथ डाटा साझा करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपका किसी दूसरे देश में कोई बैंक खाता है, रियल एस्टेट में निवेश है या फिर आपने विदेशी शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है, तो विभाग के पास पहले से ही उसकी भनक होती है। ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय इन जानकारियों को गोलमोल करना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।

विदेशी कंपनियों के शेयर पर क्या हैं नियम?

अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और आपको कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड के तौर पर शेयर मिले हैं, तो यह टैक्स का यह नियम आप पर भी पूरी तरह से लागू होता है। एसबीएचएस एंड एसोसिएट्स के फाउंडिंग पार्टनर हिमांग सिंगला इस मामले में स्पष्ट राय रखते हैं। उनका कहना है कि अगर कर्मचारियों के पास किसी भी विदेशी कंपनी के ईसॉप्स (ESOPs), आरएसयू (RSUs) या फिर सामान्य शेयर मौजूद हैं, तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को देना अब अनिवार्य हो गया है। सिर्फ शेयर ही नहीं, अगर आपको भारत के बाहर से किसी भी प्रकार की कमाई हो रही है या आपने किसी विदेशी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, तो उसे भी अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करना ही होगा। इसे नजरअंदाज करना आयकर नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा।

10 लाख रुपये का जुर्माना

अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई टैक्सपेयर जानबूझकर या अनजाने में इन विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करता है, तो क्या होगा? इसका जवाब बेहद सख्त है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में टैक्सपेयर के खिलाफ सीधे 'ब्लैक मनी' (काला धन) कानून के तहत कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

विदेशी संपत्ति और आय को छिपाने के अपराध में टैक्सपेयर पर 10 लाख रुपये तक की सीधी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। बात सिर्फ आर्थिक जुर्माने तक ही सीमित नहीं रहती। अगर मामला गंभीर पाया जाता है और अघोषित संपत्ति की रकम बहुत बड़ी होती है, तो संबंधित व्यक्ति को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जेल जाने तक का सख्त प्रावधान शामिल है। इसलिए, अपनी आईटीआर फाइल करते समय विदेशी बैंक खाते से लेकर निवेश तक का हर एक ब्यौरा पूरी ईमानदारी से दर्ज करना ही समझदारी है।

7 से ज्यादा तीव्रता के 2 झटके, 10 हजार मौतों की आशंका... वेनेजुएला में 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप

वेनेजुएला। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। प्रकृति के इस भयानक कहर ने कुछ ही सेकंड में हंसते-खेलते शहरों को मलबे के ढेर में बदल दिया है। हर तरफ चीख-पुकार, धूल का गुबार और तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागते नजर आए, जबकि कई लोग अपने ढहे हुए घरों के मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं। आइए, इन 10 तस्वीरों और वीडियो के जरिए देखते हैं कि वेनेजुएला में इस भूकंप ने कितनी गहरी और दर्दनाक चोट दी है। काराकस के लॉस पालोस ग्रांडेस इलाके में एक क्षतिग्रस्त इमारत दिखाई दे रही है। यहां कई इमारतें

गिर गई हैं, लेकिन अब तक मृतकों और घायलों की सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है।

शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जहां कभी गगनचुंबी इमारतें थीं, वहां अब सिर्फ कंक्रीट का ढेर और धूल छाई हुई है। तस्वीर काराकस के पार्के सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की है। यहां भूकंप के झटकों के बाद खुले में इंतजार करते लोग। ये लोग अपनों से फोन पर बात करते दिखे। जब भूकंप आया, तो काराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। झटकों की वजह से यहां अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। रात का समय। पूरे इलाके में बिजली गुल है, लेकिन इमरजेंसी फ्लडलाइट्स की तेज रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ड्रिलिंग मशीनों की आवाज और क्रेन से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सबसे बड़ा खतरा इमारतों और अन्य ढांचों के गिरने का है। घनी आबादी वाले इलाकों में गैस पाइपलाइन और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचने से आग भी लग सकती है। वहीं पानी की पाइपलाइन टूटने पर आग बुझाने में दिक्कत आती है। लॉस पालोस ग्रांडेस में एक क्षतिग्रस्त इमारत से बचावकर्मी एम्बुलेंस में एक घायल महिला को लेकर जाते हुए। बचावकर्मी घंटो की मेहनत के बाद मलबे से लोगों को निकाल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की एक भावुक तस्वीर। बचावकर्मी कंक्रीट के भारी स्लैब के बीच लोगों को खोज रहे हैं। जहां कभी गगनचुंबी इमारतें थीं, वहां अब सिर्फ कंक्रीट का ढेर और धूल छाई हुई है। काराकस में भूकंप के बाद ढही एक इमारत से फायरफाइटर ने कुत्ते को रेस्क्यू किया। ड्रिलिंग मशीनों की आवाज और क्रेन से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। एक परिवार अपने टूटे हुए घर के सामने खड़ा है। इस दौरान एक महिला बच्ची को गले लगाकर उसे ढांढस बंधाते दिखाई दी।

पाकिस्तान की चर्चित एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्रकैद, कोर्ट के फैसले पर मचा बवाल

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की चर्चित एक्टिविस्ट महरंग बलोच को क्वेटा की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2024 में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अर्धसैनिक जवान की हत्या और आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया। महरंग बलोच मार्च 2025 से हिरासत में हैं। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है।

क्वेटा की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने महरंग बलोच और उनके सहयोगी सिबगतुल्लाह को हत्या तथा आतंकवाद से जुड़े अपराधों में दोषी पाया। कोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 में ग्वादर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान तैनात अर्धसैनिक बल के जवान सिपाही शब्बीर बलोच की मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि महरंग बलोच ने प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए उकसाया था। फैसले में यह भी कहा गया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के दावों का समर्थन करते हैं।

महरंग बलोच लंबे समय से बलूचिस्तान में कथित जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मुकदमे की आलोचना की है। उनका कहना है कि आरोपियों को जेल से वीडियो लिंक के जरिये पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कार्यवाही का बहिष्कार किया। आलोचकों का मानना है कि इस फैसले से बलूच समुदाय और राज्य के बीच भरोसा और कमजोर हो सकता है।

वेनेजुएला के बाद अब जापान में आया 6 .9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, टोक्यो तक महसूस हुए झटके

टोक्यो, एजेंसी। वेनेजुएला में भारी तबाही मचाने के बाद अब जापान के उत्तरी हिस्से में भी धरती कांपी है। गुरुवार को जापान में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी टोक्यो तक महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि अधिकारियों ने किसी की जान जाने की खबर नहीं दी है। प्रशासन ने सुनामी की कोई चेतावनी भी जारी नहीं की है।

मौसम विभाग के अनुसार, भूकंप का केंद्र होंशू द्वीप के इवाते प्रांत के पास जमीन से 50 किलोमीटर नीचे था। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इवाते प्रांत में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया। पड़ोसी ओमोरी प्रांत के हाशिकामी शहर में झटके सबसे ज्यादा तेज थे। वहां की एक महिला ने बताया कि इन झटकों से उनके घर में एक फोटो फ्रेम भी गिर गया, बाकी सुरक्षित है। सार्वजनिक प्रसारक एनएचके के फुटेज में हाचिनोहे शहर में यातायात सामान्य दिखा और ट्रैफिक लाइटें भी सही से काम कर रही थीं। सरकारी प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने कहा कि फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। होक्काइडो द्वीप पर स्थित तोमारी परमाणु संयंत्र के पास रेडिएशन की जांच की गई, जहां सब कुछ सामान्य मिला है। ओमोरी में भूकंप की तीव्रता जापान के सात-स्तरीय पैमाने पर 'अपर सिक्स' दर्ज की गई। इस स्तर पर लोग बिना सहारे के खड़े नहीं रह पाते और गिर सकते हैं। साथ ही, भारी फर्नीचर गिर सकता है और खिड़कियों के कांच टूट सकते हैं। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने सभी मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की कि वे आने वाले समय में और झटकों की आशंका को देखते हुए सतर्क रहें। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है।

ट्रंप की नई डिमांड, ईरान युद्ध से जुड़े खर्च के लिए 87 अरब डॉलर की फंडिंग मांगी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से 87 ।6 अरब डॉलर (करीब 8 ।25 लाख करोड़ रुपये) की अतिरिक्त राशि मंजूर करने की मांग की है। इस पैसे का बड़ा हिस्सा ईरान के साथ हुए युद्ध और उससे जुड़े सैन्य खर्चों पर खर्च किया जाएगा। इस मांग के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रस्ताव के मुताबिक, कुल राशि में से 67.15 अरब डॉलर (करीब 6.33 लाख करोड़ रुपये) रक्षा और सैन्य जरूरतों के लिए मांगे गए हैं।

यह रकम उस लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट के अलावा है, जिसे पिछले साल मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन अगले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नया

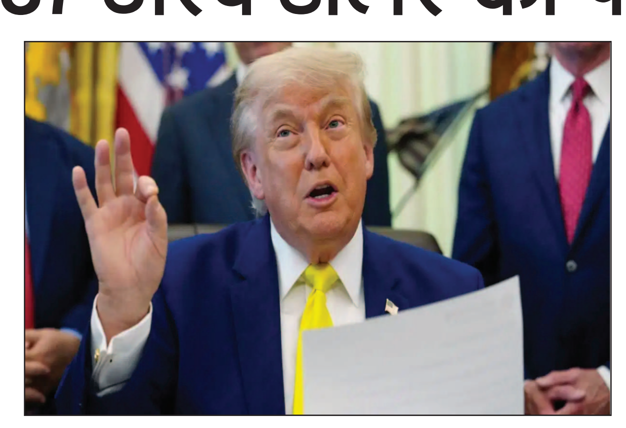

रक्षा बजट भी मांग रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह पैसा ईरान युद्ध से जुड़े सैन्य अभियानों, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को दोबारा भरने और कुछ गोपनीय रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च होगा। इसमें से 21 अरब डॉलर (करीब 1.98 लाख करोड़ रुपये) गोला-बारूद खरीदने, अमेरिकी रक्षा उत्पादन बढ़ाने और सेना की ताकत मजबूत करने के लिए रखे गए हैं।

सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास

इस बीच कांग्रेस में युद्ध को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) भी पास कर चुकी है। कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया।

बुधवार को रिपब्लिकन पार्टी की बैठक के दौरान ट्रंप और रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी के बीच तीखी बहस हुई। कैसिडी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया था। दोनों पार्टियों के कई सांसदों का कहना है कि सरकार ने युद्ध से जुड़ी पूरी जानकारी संसद को नहीं दी। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस को भरोसे में लिए बिना कई सैन्य फैसले किए हैं।

अतिरिक्त खर्च की जांच की मांग

डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि सरकार को युद्ध पर इतना पैसा खर्च करने के बजाय देश की आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने इस प्रस्ताव की आलोचना की, जबकि सीनेटर पैटी मरे ने कहा कि सैनिकों का समर्थन जरूरी है, लेकिन अतिरिक्त युद्ध खर्च की पूरी जांच होनी चाहिए। इस पैकेज में सिर्फ रक्षा खर्च ही नहीं है। इसमें अफ्रीका में इबोला बीमारी से निपटने के लिए 1.4 अरब डॉलर, अमेरिकी किसानों की मदद के लिए 11.1 अरब डॉलर, पूर्व डेल्फी कर्मचारियों की पेंशन के लिए 1 अरब डॉलर, वॉशिंगटन की निर्माण परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ डॉलर और न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब डॉलर भी शामिल किए गए हैं।

बजट के तीन महीने बाद पूरक मांगें क्यों? शिवसेना (यूबीटी) ने महायुति सरकार को घेरा, पूछे ये सवाल

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने बजट पेश होने के महज तीन महीने बाद ही 97,706.40 करोड़ रुपए की पूरक मांगें पेश कर दी हैं। पार्टी के अनुसार यह कदम राज्य के गिरते वित्तीय अनुशासन को साफ तौर पर उजागर करता है। पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में लिखा गया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। राज्य पर सार्वजनिक कर्ज करीब 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हर साल केवल ब्याज चुकाने में ही 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार सरकारी खजाने से मनमाने ढंग से पैसा लुटा रही है।

संपादकीय में सरकार की तुलना उस छात्र से की गई है जो परीक्षा में एक के बाद एक सप्लीमेंट्री कॉपी जोड़ता है, लेकिन अंत में मुश्किल से पास हो पाता है। शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि बजट के तुरंत बाद इतनी बड़ी रकम की मांग करना किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। पिछले चार वर्षों में महायुति सरकार ने लगभग पांच लाख करोड़ रुपए की पूरक मांगें पेश की हैं। पार्टी ने इसे बजट से अधिक खर्च करने का एक विश्व रिकॉर्ड बताया है।

पार्टी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मुख्य बजट में जरूरी आवंटन छिपाती है। बाद में राजनीतिक फायदे के लिए पूरक मांगों के रास्ते हजारों करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। इस बार तो सरकार ने सारी हदें पार कर दीं। अगले बजट में अभी नौ महीने बाकी हैं, लेकिन सरकार के राजस्व और खर्च के अनुमान पहले तीन महीनों में ही फेल हो गए।

संपादकीय में पुरानी बातों को भी याद दिलाया गया। जब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार सत्ता में थी, तब मौजूदा सत्ताधारी नेता विपक्ष में थे। उस समय वे बहुत कम रकम की पूरक मांगों पर भी सरकार की कड़ी आलोचना करते थे। वे इसे वित्तीय अनुशासन का पतन बताते थे। आज वही नेता मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पदों पर बैठे हैं। अब उन्हें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूरक मांगें वित्तीय अनुशासनहीनता नहीं लगतीं।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार पूरक मांगों का नया रिकॉर्ड बना रही है। महाराष्ट्र कभी अपने वित्तीय अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। पिछले चार वर्षों में यह साख पूरी तरह खत्म हो गई है। सरकार राज्य की उस आर्थिक विरासत को खुलेआम नष्ट कर रही है, जिसे कभी ईमानदारी के लिए सम्मान मिलता था। शिवसेना ने कहा कि अनुत्पादक कामों पर अंधाधुंध खर्च ने राज्य की वित्तीय योजना को पटरी से उतार दिया है।

इबोला अलर्ट के बीच भारत ने लॉन्च किया 'एयर सुविधा 2.0', ऑनलाइन जमा होगी यात्रा डिटेल

नई दिल्ली, एजेंसी। इबोला वायरस अफ्रीका से दुनियाभर के ज्यादातर देशों में लगातार फैलता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट है। भारत में भी इस पर सतर्कता बरती जा रही है। इबोला से प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए अब 'एयर सुविधा पोर्टल' शुरू कर दिया गया है।

भारत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा 2.0' (AIR SUVIDHA 2.0) लॉन्च करके अपने एयरपोर्ट हेल्थ सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। यह यात्रियों की सेहत से जुड़ी जानकारी देने वाला पूरी तरह से डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है। यात्री अब प्लेन से उतरने से पहले ही जरूरी 'सेल्फ़-डिक्लेरेशन फ़ॉर्म' (SDF) आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे पहले की कागजी प्रक्रिया की जगह अब ऑनलाइन जानकारी दी जा सकेगी।

उड्डयन मंत्रालय ने DIAL के साथ किया लॉन्च

इस अपग्रेडेड पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसे तब लॉन्च किया लाया गया जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में इबोला या बुंडिबुग्यो वायरस बीमारी के सामने आने के बाद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस (IHR) 2005 के तहत 'इंटरनेशनल कन्सर्न ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' (PHEIC) घोषित कर दिया है। हालांकि इबोला की बात सामने आने पर स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि संक्रामक बीमारियों को देश में आने और फैलने से रोकने में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की शुरुआती पहचान और निगरानी अहम भूमिका निभाती है। चूंकि ग्लोबल ट्रैवल की वजह से बीमारियां तेजी से एक देश से दूसरे देश में फैलती हैं। ऐसे में 'एयर सुविधा' जैसे डिजिटल सर्विलांस सिस्टम स्वास्थ्य को लेकर एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं।

यात्रा शुरू करने से 24 घंटे पहले भरना होगा फॉर्म

माना जा रहा है कि यह नया प्लेटफॉर्म प्रशासन के लिए उन यात्रियों की पहचान करने में मदद कर सकता है जिन्हें इससे खतरा हो सकता है, साथ ही भारत आने वाले यात्रियों के लिए बिना किसी परेशानी के आना-जाना संभव हो सकेगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, कांगो और युगांडा में इबोला के मामले सामने आने के बाद इस अपग्रेडेड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। WHO ने पिछले महीने 17 मई को इस वायरस से आने के बाद 'इंटरनेशनल कन्सर्न ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' घोषित किया था। नया मामला बुंडिबुग्यो वायरस बीमारी (BVD) के तौर पर हुई है, जो इबोला वायरस बीमारी की ही एक प्रजाति है और प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर बीमारी और तेजी से फैलने की वजह बनती है। इस फॉर्म में 21 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही अगर किसी तरह का कोई लक्षण हों, तो उनकी भी जानकारी देनी होती है। फ़ॉर्म को भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले तक भरा जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इसे यात्रा शुरू करने से पहले, बेहतर होगा कि वेब चेक-इन के समय ही जमा कर दें। फ़ॉर्म भरने के बाद, यात्रियों को बस डाउनलोड किया हुआ 'सेल्फ-डिक्लेरेशन फ़ॉर्म' इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्थ डेस्क या इमिग्रेशन काउंटर पर दिखाना होगा।

कुणाल खेमू के शो अलायंस का ट्रेलर जारी, विषय और प्रतियोगियों के चेहरों से उठा पर्दा

कॉमेडी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल करने वाले कुणाल खेमू रियलिटी शो अलायंस की मेजबानी करेंगे। यह पहली बार होगा, जब वह शो में प्रतियोगियों की मुश्किलें बढ़ाते और उन्हें आपस में लड़ाते हुए दिखेंगे। कुछ दिन पहले शो का आधिकारिक ऐलान हुआ था और अब इसका धमाकेदार ट्रेलर भी जारी हो गया है। ट्रेलर में शो का विषय (थीम) और आने वाले प्रतियोगियों के चेहरे उजागर किए गए हैं। बता दें, अलायंस 26 जून से अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगा।

ट्रेलर में बताया गया है कि शो में 16 प्रतियोगी 2-2 की जोड़ियों में शामिल होंगे। इसका विषय दोस्ती, गहरी रणनीति और धोखे पर आधारित होगा। मतलब यह कि प्रतियोगियों को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपने गुट को तोड़ना होगा। रवि किशन अपनी बेटी रीवा किशन के साथ हिस्सा लेंगे। कुशाल टंडन, जैद दरबार, डेज़ी शाह, नीति टेलर और सिवेट तोमर समेत कई सितारे भी इसका हिस्सा हैं। शो के एपिसोड रोजाना दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होंगे।

इस शो के बारे में बात करते हुए , कुणाल खेमू ने शेयर किया, एलायंस किसी भी ऐसे रियलिटी शो जैसा नहीं है जिसे मैं जानता हूं। जो बात इसे इतना रोमांचक बनाती है वो ये है कि यह सिर्फ चैलेंजेस जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि रिश्तों को निभाने, मुश्किल फैसले लेने और खेल के बदलते ही खुद को उसके हिसाब से ढालने के बारे में है। एक रियलिटी सीरीज को होस्ट करने के मेरे इस पहले अनुभव में, हर दिन सामने आने वाली इस इंटेंसिटी , स्ट्रैटेजी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखना बेहद रोमांचक रहा है। इतने महत्वाकांक्षी और इनोवेटिव फॉर्मेट पर प्राइम वीडियो के साथ पार्टनरशिप करना वाकई बहुत खास रहा है। मैं दर्शकों के एलायंस की दुनिया में कदम रखने और भरोसे, ताकत और सर्वाइवल के इस हाई-स्टेक्स खेल का अनुभव करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं, जब इसका प्रीमियर 26 जून को प्राइम वीडियो पर होगा।

कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस : दुनिया भर में 100 करोड़ के आंकड़े के करीब शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म, मंडे टेस्ट में हुई 6.35 करोड़ की कमाई

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म कॉकटेल 2 दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। फिल्म अपनी रिलीज के चार दिन पूरे कर चुकी है और आज मंगलवार को रिलीज के पांचवें दिन में चल रही है। आलोचकों और दर्शकों से मिली-जुली रिव्यू के बावजूद, इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और सिर्फ चार दिनों में वर्ल्डवाइड 85 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

हालांकि फिल्म ने पहले सोमवार यानी मंडे टेस्ट में कमाई में अपेक्षित गिरावट दर्ज की, फिर भी यह हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक है।

बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, कॉकटेल 2 ने भारत में चौथे दिन 9,785 शो में 6.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 64.56 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका नेट कलेक्शन अब 53.85 करोड़ रुपये है।

ओवरसीज में, फिल्म ने सोमवार को 1.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही, फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 85.31 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और अब यह 100 करोड़ रुपये के आंकड़े से 15 करोड़ रुपये से भी कम रह गई है।

फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रतिक्रिया मिली और पहले वीकेंड में इसकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। पहले शुक्रवार को इस रोमांटिक कॉमेडी ने 16.20 करोड़ रुपये का सकल राजस्व और 13.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।

शनिवार को कुल कलेक्शन बढ़कर 19.50 करोड़ रुपये ग्रॉस और 16.25 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हुआ, जो रविवार को बढ़कर 21.20 करोड़ रुपये ग्रॉस और 17.50 करोड़ रुपये नेट के शिखर पर पहुंच गया। सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने पांचवें दिन खबर लिखे जाने तक 0.41 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन भी पार कर लिया है। इस दौरान इसने वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के भारत में हुए नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 50.60 करोड़ रुपये कमाए थे।

कॉकटेल 2 ने आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो के भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है , जो 51.35 करोड़ रुपये था। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित फिल्म कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की पटकथा लव रंजन और तरुण जैन ने लिखी है और दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले इसका निर्माण किया है।

यह फिल्म 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल की एक तरह से अगली कड़ी है , जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

पंचायत सीजन 5 में होंगे कई धमाकेदार ट्विस्ट, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और अशोक पाठक ने खोले राज

टीवीएफ की पंचायत सबसे पसंदीदा सीरीज में से एक है। इसके हर एक एपिसोड ने अपनी दिलचस्प और शानदार कहानी से दर्शकों को बांधे रखा है। हाल ही में एक समिट के दौरान, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और अशोक पाठक ने सीरीज के इस सबसे बहुप्रतीक्षित अगले चैप्टर पर खुलकर बात की। पूर्व विपक्ष के दोबारा सत्ता में आने के बाद फुलेरा के बदलते समीकरणों पर रोशनी डालते हुए, एक्टर्स ने यह हिंट दिया कि आगे गांव में क्या होने वाला है।

कहानी के बड़े राज छिपाकर रखते हुए, उन्होंने इशारा किया कि पंचायत सीजन 5 कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो पिछले सीजन्स के मुकाबले एक बिल्कुल अलग और मजेदार अनुभव देने का वादा करता है।

बनराकस (भूषण) का रोल निभाने वाले दुर्गेश कुमार, जिन्होंने बृज भूषण और मंजू देवी को हराकर ग्राम पंचायत पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है, पंचायत 5 के प्लॉट पर बात करते दिखे। हालांकि, उन्होंने कहा, ऐसे तो नहीं बता सकते, वरना ऑडियंस का कॉमिक टाइमिंग खराब हो जाएगा। लेकिन, इस बार भी आनंद आने वाला है।

दुर्गेश की बात को दोहराते हुए, अशोक पाठक उर्फ बिनोड ने शेयर किया, मज़ा आएगा। इस बार का सीजन कुछ अलग, हटके होगा। रोमांच ज़्यादा होने वाला है। पंचायत सीजन 4 एक बेहद दिलचस्प मोड़ (क्लिफहैंगर) पर खत्म हुआ था, जिसने दर्शकों को यह जानने के लिए बेताब छोड़ दिया कि नए चुने हुए नेतृत्व में आखिरकार फुलेरा की कमान कौन संभालेगा।

गांव के अगले उप-प्रधान की पहचान अभी भी रहस्य के घेरे में है, ऐसे में आने वाले सीजन से यह सस्पेंस खुलने और फुलेरा के राजनीतिक समीकरणों के सामने आने की उम्मीद है। जब इस बारे में पूछा गया, तो फुलेरा की नई प्रधान, क्रांति देवी का रोल निभाने वाली सुनीता राजवार ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, घर की बात, घर में ही रहेगी। वो हम आपको स्टेज पे नहीं बताएंगे। हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है।

सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक मेंटेन करना, गांव की सरलता भी मेंटेन करना, मसाला भी मेंटेन करना। उनकी लिखावट और हम कलाकारों की कारीगरी एक साथ स्क्रीन पे देखने में मजा आएगा। अभी बता देंगे तो मज़ा खत्म हो जाएगा।

पंचायत के एक्टर्स ने शो के अगले सीजन के लिए उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया है। हालांकि पंचायत सीजन 5 की रिलीज डेट का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन अमेज़न प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि नए एपिसोड इसी महीने से स्ट्रीम होना शुरू हो जाएंगे।

इसके अलावा, पंचायत को न केवल दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवाड्र्स 2025, आईफा डिजिटल अवाड्र्स 2025 (पहला एडिशन) और आइकॉनिक गोल्ड अवाड्र्स 2026 जैसे कई पुरस्कार मिले हैं, बल्कि यह सोशल मीडिया पर भी एक वायरल सनसनी बन चुका है। असल में, इसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को जितेंद्र कुमार और फैसल मलिक जैसे कुछ बेहतरीन एक्टर्स से रूबरू कराया है।

साल 2020 में पहली बार लॉन्च हुई पंचायत, ग्रामीण भारत के अपने असली चित्रण और एक गांव के पंचायत सचिव के रूप में काम करने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के इर्द-गिर्द बुनी गई रिलेटेबल कहानी की वजह से बहुत जल्द लोगों की पसंदीदा बन गई। पिछले कुछ सालों में, इस सीरीज ने अपनी सादगी, ह्यूमर और इमोशनल डेप्थ (भावनात्मक गहराई) के लिए क्रिटिक्स से खूब तारीफें बटोरी हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com